सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh
YouTube

Title Code : DELHIN28985.
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.parivahanvishesh.com

परिवहन विशेष

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

वर्ष 01, अंक 176, नई दिल्ली | शुक्रवार, 08 सितम्बर 2023, मूल्य ₹ 5, पेज 8

आज का सुविचार

कभी जल्दी हार ना मानो, कई बार गुच्छे की आखिरी चाबी से ताला खुलता है।

G20 Summit: राजधानी तैयार है, जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम; सुबह से बंद रहेंगी ये सड़कें

एनएसजी ने प्रगति मैदान समेत दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह संभाल लिया है। दूसरी तरफ गुरुवार रात से प्रगति मैदान टनल को बंद कर दिया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने लोगों को नई दिल्ली व मध्य दिल्ली के कुछ हिस्सों में न जाने की सलाह दी है।

संजय बाटला, संपादक

नई दिल्ली। महीनों से चल रही तैयारियों के बाद देश की राजधानी दिल्ली जी-20 सम्मेलन के लिए तैयार है। सम्मेलन व विदेशी मेहमानों की सुरक्षा जमीन से लेकर आसमान तक इस कदर कड़ी की गई है कि अगर एक तिनका भी आसमान/जमीन पर उड़ेगा तो उसे भी पकड़ लिया जाएगा। दिल्ली में चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा जवान हैं।

एनएसजी ने प्रगति मैदान समेत दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह संभाल लिया है। दूसरी तरफ गुरुवार रात से प्रगति मैदान टनल को बंद कर दिया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने लोगों को नई दिल्ली व मध्य दिल्ली के कुछ हिस्सों में न जाने की सलाह दी है। पुलिस का कहना है कि लोग मेट्रो से यात्रा करें और मैप माई इंडिया एप पर नेवीगेशन लगाकर बंद रास्तों के बारे में पता कर लें। गुरुवार रात से ही नई दिल्ली की सड़कों पर सन्नाटा पसरने लग गया था।

जी-20 सम्मेलन के दौरान कई रास्ते बंद मथुरा रोड, भैरो मार्ग व रिंग रोड को शुक्रवार सुबह से बंद कर दिया जाएगा। प्रगति मैदान टनल को भी गुरुवार रात से आम यात्री व वाहनों के लिए बंद कर दिया जाएगा। प्रगति मैदान टनल मथुरा रोड से लेकर इंडिया गेट, सुप्रीम कोर्ट और आईटीओ की ओर जाने वाले मार्गों को जोड़ती है। इस कारण इन मार्गो पर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि पुलिस ने जो एडवाइजरी जारी है कि उसके अनुसार यात्रा करें व उसका पालन करें।

सम्मेलन में शामिल होने वाले विदेशी मेहमानों का दिल्ली आना शुरू हो गया है। पूरे नई दिल्ली इलाके में हजारों सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इन कैमरों को कंट्रोल रूम पुलिस मुख्यालय की छठी मंजिल पर बनाया गया है। यहां पर 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी सीसीटीवी कैमरों से जुड़ी स्क्रीन पर नजर रख कर सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखे हुए हैं। नई दिल्ली के हर पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरों का कंट्रोल रूम बनाया गया है। इन कंट्रोल रूम से पुलिस स्टेशन क्षेत्र पर कड़ी नजर रखी जा रही है। होटलों में भी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। विदेशी मेहमान इन कैमरों की जद में खाना व नाश्ता करेंगे। रायसीना रोड से प्रेस क्लब तक के मार्ग को बंद कर दिया गया है।

इन बातों का रखें ध्यान

-पर्याप्त समय लेकर चलें। अपने वाहन का इस्तेमाल न करें। मेट्रो सफर के लिए बेहतर रहेगी।

-नई दिल्ली स्टेशन को इंदिरा गांधी

अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे टी-3 के माध्यम से द्वारका सेक्टर-21 स्टेशन से जोडने वाली एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन (ऑरेंज लाइन) का इस्तेमाल करें।

-अंतरराज्यीय बसों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। सभी बसों का समापन रिंग रोड पर ही होगा।

-दिल्ली में पहले से मौजूद बसें रिंग रोड और रिंग रोड से आगे दिल्ली की सीमाओं की ओर के सड़क नेटवर्क पर संचालित होंगी। इन्हें दिल्ली से बाहर निकलने की अनुमति होगी।

-नई दिल्ली में ऑटो व टैक्सी आवश्यक सर्विस को छोड़कर आने की अनुमति नहीं होगी।

-एयरपोर्ट, नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशनों तक यात्रियों को आवाजाही की अनुमति रहेगी।

-नई दिल्ली जिले में प्रवेश करने वाले यातायात की आवाजाही को नियंत्रित किया जाएगा।

-स्थानीय निवासियों और अधिकृत वाहनों को नई दिल्ली जिले के भीतर आवागमन की अनुमति होगी।

-नई दिल्ली जिले में होटलों, अस्पतालों और अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के लिए हाउस कीपिंग, खानपान, अपशिष्ट प्रबंधन आदि से जुड़े वाहनों को सत्यापन के बाद प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।

-मालवाहक वाहनों और बसों को छोड़कर सामान्य यातायात को रजोकरी सीमा से दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके अलावा, इस यातायात को अनिवार्य रूप से एनएच-48 से राव तुला राम मार्ग—पाल्मे मार्ग पर भेजा जाएगा। एनएच-48 पर धौला कुआं की ओर किसी भी वाहन की आवाजाही की अनुमति नहीं होगी।

-10 सितंबर बी सुबह 5 बजे से दोपहर 1 बजे तक नियंत्रित क्षेत्र-दो में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, अजमेरी गेट की ओर से पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोड की ओर से शांति वन चौक, गीता कॉलोनी की ओर से आईटीओ, विकास मार्ग की ओर से राजघाट चौक, जवाहर लाल नेहरू (जेएलएन) मार्ग, गुरु नानक चौक, मिंटो रोड की ओर से पूरी तरह बंद रहेंगे।

यहां बताएं अपनी परेशानी

पुलिस ने अपील की है कि आम जनता और वाहन चालक धैर्य रखें, यातायात नियमों और सड़क अनुशासन का पालन करें। सभी चौराहों पर तैनात यातायात कर्मियों के निर्देशों का पालन करें और दिल्ली यातायात पुलिस की वेबसाइट https://traffic.delhipolice.gov.in, फेसबुक पेज https://www.facebook.com/dtptraffic, ट्विटर हैंडल https://twitter.com/dtptraffic, इंस्टाग्राम पेज https://www.instagram.com/dtptraffic, व्हाट्सएप नंबर 8750871493 और हेल्पलाइन नंबर 1095/011—25844444 के माध्यम से अपडेट रहें।

एयरपोर्ट पर कदम रखते ही संस्कृति से होंगे रूबरू

नई दिल्ली। विदेशी मेहमानों का स्वागत दिल्ली का गेटवे कहे जाने वाले एयरपोर्ट से ही शुरू हो जाएगा। जी-20 शिखर सम्मेलन के लिए पहुंचने वाले राष्ट्राध्यक्षों का भव्य स्वागत किया जाएगा, साथ ही वह भारत में कदम रखते ही यहां की संस्कृति से रूबरू होंगे। उनके सम्मान में सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया जाएगा। भारतीय शास्त्रीय गीत-संगीत और नृत्य से परिचित कराया जाएगा। भारतीय परंपराओं से अवगत कराने के लिए विशेष चित्रकारी इंटरनेशनल सिरोमोनियल लाउंज में की गई है। एयरपोर्ट पर इस तरह के लाउंज-एक तो टेक्निकल एरिया में तैयार किया गया है, दूसरा टर्मिनल परिसर में। यहां इमिग्रेशन विभाग पूरी तरह सक्रिय रहेगा। एयरपोर्ट के टर्मिनल को खासतौर से सजाया गया है। अतिथि पालम की ओर वायु सेना स्टेशन पर पहुंचेंगे, कई अन्य राष्ट्राध्यक्षों के साथ-साथ अन्य प्रतिनिधिमंडल के सदस्य भी टर्मिनल-3 पर आने वाले हैं, उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। हर विदेशी मेहमान के लिए समर्पित गेट को खूबसूरती से डिजाइन किया गया है। सभी मेहमानों के लिए एक समर्पित गलियारा बना है। झरने और फव्वारे लगाए गए हैं जो आने वाले राष्ट्राध्यक्षों और प्रतिनिधियों को सुखद अनुभव देंगे। जी-20 की ब्रांडिंग होगी, कई स्थानों पर विशेष लाइटें आगमन और प्रस्थान रैंप पर लगी हैं। तिरंगा रंग की लाइटें हर जगह लगी हैं।

मेहमानों के लिए एक अलग गेट होगा

डायल के सीईओ विदेह कुमार जयपुरियार ने बताया कि दिल्ली एयरपोर्ट पर 8 सितंबर को विदेशी मेहमान आएंगे। इनमें अधिकांश मेहमानों के 10 सितंबर को जाने की संभावना है। जहां तक शहर की तरफ यातायात का सवाल है, कुछ व्यवधान होने वाले हैं। दिल्ली से उड़ान भरने वाले यात्रियों को सलाह दी है कि वे सार्वजनिक परिवहन से आना-जाना सुनिश्चित करें। मेट्रो को प्राथमिकता दें। मेहमानों के स्वागत के लिए एयरपोर्ट तैयार है। डेलिगेट के लिए एक अलग गेट होगा, ताकि वे जल्द से जल्द इमीग्रेशन और कस्टम क्लीयर कर सकें। उन्होंने बताया कि इससे सामान्य यात्रियों को कोई असुविधा नहीं होगी।

एयरसाइट में चार्टर्ड उड़ानों के लिए विशेष तैयारी की गई है। दिल्ली पुलिस समेत विभिन्न सरकारी एजेंसियों के साथ नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के सहयोग से इन उड़ानों के लिए हवाई क्षेत्र में ही पार्किंग की व्यवस्था की है।

G-20 सम्मिट: तीन दिन दिल्ली बंद! शिखर सम्मेलन के दौरान खुले रहेंगे अस्पताल, सामान्य रूप से चलेगी ओपीडी

परिवहन विशेष न्यूज

जी 20 सम्मेलन के दौरान सरकारी विभागों में अवकाश के बावजूद एम्स व सफदरजंग के साथ-साथ नई दिल्ली के इलाके में स्थित अस्पताल खुले रहेंगे। इस दौरान अस्पताल में ओपीडी सेवाएं जारी रहेगा। एम्स सहित दिल्ली के नौ प्रमुख सरकारी अस्पतालों में आपात स्थिति से निपटने और विदेशी मेहमानों के इलाज के लिए आइसीयू सहित 325 से अधिक बेड आरक्षित रखे गए हैं।

नई दिल्ली। जी 20 सम्मेलन के दौरान सरकारी विभागों में अवकाश के बावजूद एम्स व सफदरजंग के साथ-साथ नई दिल्ली के इलाके में स्थित आरएमएल अस्पताल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के सुचेता कृपलानी व कलावती सरन अस्पताल भी खुले रहेंगे। इसलिए सामान्य दिनों की तरह अस्पतालों की ओपीडी में डॉक्टर मौजूद रहेंगे।

सर्जरी की कम होने की संभावना

ओपीडी का संचालन सामान्य तौर पर होगी, लेकिन कई सड़कों से आवागमन बंद होने के कारण मरीजों के कम ही पहुंचने की संभावना है। इसके अलावा रूटीन सर्जरी भी कम हो सकती है। सफदरजंग अस्पताल प्रशासन से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि अस्पताल में जी 20 सम्मेलन के मद्देनजर की गई तैयारियों को ध्यान में रखते हुए पिछले तीन-चार दिनों से आठ और नौ सितंबर को सर्जरी की नई तारीख नहीं दी गई है।

आपात स्थिति से निपटने के लिए 325 बेड आरक्षित

ऐसे में सर्जरी कम होने की संभावना है। आरएमएल व लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों में मरीजों को पहुंचने में दिक्कत हो सकती है। इस वजह से इन अस्पतालों में मरीजों के कम ही पहुंचने की संभावना है। एम्स सहित राष्ट्रीय राजधानी के नौ प्रमुख सरकारी अस्पतालों में आपात स्थिति से निपटने और विदेशी मेहमानों के इलाज के लिए आइसीयू सहित 325 से अधिक बेड आरक्षित रखे गए हैं।

इसमें एम्स, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सफदरजंग, आरएमएल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज का सुचेता कृपलानी अस्पताल व दिल्ली सरकार के पांच बड़े अस्पताल शामिल हैं। इन अस्पतालों की इमरजेंसी में सामान्य दिनों के मुकाबले अतिरिक्त डाक्टर तैनात रखे गए हैं। इसके अलावा निजी क्षेत्र के अपोलो, प्राइमस, मैक्स साकेत व मणिपाल अस्पताल में भी इलाज की व्यवस्था की गई है।

सीबीआरएन (केमिकल, बायोलाजिकल, रेडियोलाजिकल व न्यूक्लियर) हमले जैसी आपात स्थिति से निपटने के लिए भी अस्पतालों में तैयारी की गई है। एम्स को न्यूक्लियर, सफदरजंग अस्पताल को रसायनिक व आरएमएल को जैविक हमले की स्थिति में इलाज का नोडल सेंटर बनाया गया है। आर्मी के साथ मिलकर इन तीनों अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था की गई है।

इन अस्पतालों के गेट के बाहर हेल्प डेस्क बनाई गई। डी-कंटेमिनेशन के लिए शावर की व्यवस्था की गई है और आर्मी की मेडिकल टीम भी तैनात की गई है। एम्स प्रशासन का कहना है कि ट्रामा सेंटर और मुख्य अस्पताल की आइसीयू बेड और प्राइवेट वार्ड में कमरे आरक्षित रखे गए हैं। दोनों जगहों को मिलाकर एम्स में करीब 50 बेड आरक्षित रखे गए हैं।

जरूरत पड़ने पर हादसे व सीबीआरएन से संबंधित मामले ट्रामा सेंटर में और किसी की तबीयत खराब होने पर सामान्य इमरजेंसी से संबंधित मामले मुख्य अस्पताल में देखे जाएंगे। प्राइवेट वार्ड में अत्याधुनिक व्यवस्था की गई है। सफदरजंग अस्पताल ने सीबीआरएन से संबंधित मामलों के लिए बर्न सेंटर में व्यवस्था की है। सफदरजंग, आरएमएल व लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज के अस्पताल में आठ से दस सितंबर तक डाक्टरों व पैरामेडिकल कर्मचारियों की छुट्टियां रद है।

निजी क्षेत्र के अस्पतालों में भी व्यवस्था

इसलिए सभी डॉक्टर व कर्मचारी ड्यूटी पर तैनात रखेंगे। निजी क्षेत्र के अपोलो अस्पताल में 25 बेड और एडवांस लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस तैयार रखी गई है। एयरपोर्ट के नजदीक स्थित द्वारका के मणिपाल अस्पताल में भी करीब बेड व एंबुलेंस तैयार रखी गई है।

डॉक्टरों व पैरामेडिकल कर्मचारियों की 80 टीमें तैनात सम्मेलन में शामिल होने के लिए आने वाले मेहमानों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए डाक्टरों व पैरामेडिकल कर्मचारियों की 80 टीमें लगाई गई है। मेहमानों के ठहरने के लिए निर्धारित होटल और आयोजन स्थल के पास 24 घंटे डॉक्टरों व पैरामेडिकल कर्मचारियों की टीम की की ड्यूटी लगाई है। 76 अत्याधुनिक जीवन रक्षक उपकरणों से लैस एंबुलेंस को मिलाकर 106 एंबुलेंस महत्वपूर्ण जगहों पर तैनात की गई हैं। ताकि जरूरत पड़ने पर जल्दी चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराई जा सके।

अस्पतालों में आरक्षित बेड व कमरे

एम्स व ट्रामा सेंटर- करीब 50 बेड

सफदरजंग अस्पताल की इमरजेंसी व आपदा वार्ड-32 बेड

आरएमएल की इमरजेंसी व नर्सिंग होम-62

लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज के अस्पताल के आपदा वार्ड- 30 बेड

जीटीबी अस्पताल-20 बेड

दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल-65 बेड

बाबा साहेब आंबेडकर अस्पताल -40 बेड

लोकनायक अस्पताल-20 कमरे

जीबी पंत अस्पताल-10 कमरे

गाजियाबाद की सीमाएं सील, 10 सितंबर तक दिल्ली में वाहनों की एंट्री बैन

शिखर सम्मेलन को लेकर गाजियाबाद-दिल्ली बार्डर पर रूट डायवर्जन लागू रहेगा। एडीजी यातायात बीबी पालसन ने बुधवार को जिला के यातायात पुलिस अधिकारियों के साथ रूट प्लान देखा। पुलिस उपायुक्त ने कहा कि रूट के पास 650 दुकानदार और 150 रेहड़ी-पटरी वालों को नोटिस जारी किया गया है। उन्हें हिदायत दी गई है कि वह दुकान के बाहर किसी तरह की भीड़ न लगाए।

गाजियाबाद। दिल्ली में होने वाले जी-20 सम्मेलन के चलते आज शाम 7:00 बजे से दिल्ली-यूपी की सभी सीमाएं पूरी तरह से सील कर दिया गया है। अब यूपी गेट, आनंद विहार, सीमापुरी बॉर्डर, तुलसी निकेतन बॉर्डर, खजूरी पुस्ता बॉर्डर से वाहनों को दिल्ली में एंट्री नहीं मिलेगी।

10 सितंबर को कार्यक्रम की समाप्ति तक ये डायवर्सन डायवर्जन लागू रहे। ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे से वाहन अपने-अपने गंतव्य को जाएंगे। हालांकि, आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को आने जाने की अनुमति होगी।

पुलिस ने जी-20 रूट पर किया अभ्यास

विदेशी मेहमानों की सुरक्षा के मद्देनजर बुधवार को पुलिस ने जी-20 रूट पर अभ्यास किया। विदेशी नागरिकों की गाड़ी के साथ एंबुलेंस और सुरक्षाकर्मियों की 10 गाडियां चलेंगी। पुलिस उपायुक्त ट्रांस हिंडन शुभम पटेल ने बताया कि अभ्यास के दौरान पुलिस की गाड़ियां एयरपोर्ट से निकलकर यूपी गेट तक पहुंची।

जी-20 रूट पर 150 कट पर यातायात पुलिसकर्मी तैनात रहे। पुलिसकर्मियों ने बैरियर लगाकर वाहनों को रोका। करीब 40 मिनट तक अभ्यास किया गया। सात से 10 सितंबर तक सड़क किनारे लोगों को खड़े होने की अनुमति नहीं होगी।

एयरपोर्ट के पास छतों पर 200 पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात

कोई रेहड़ी-पटरी वाले इस रूट के पास नजर नहीं आएगा। एयरपोर्ट के पास छतों पर 200 पुलिसकर्मी अत्याधुनिक हथियारों के साथ तैनात रहेंगे। रूट प्लान से भारी व हल्के वाहन दिल्ली में प्रवेश नहीं करेंगे। जब विदेशी मेहमानों का काफिला निकलेगा तो यातायात को रोका जाएगा।

ये रहेगा डायवर्जन प्लान

दिल्ली के गैर गंतव्य वाहनों का प्रवेश दिल्ली सीमा में पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। सभी वाहन ईस्टर्न पेरिफेरल से होकर निकाले जाएंगे।

बुलंदशहर की तरफ से आने वाले वाहनों को लालकुआं से एनएच-9 से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे से होकर निकाला जाएगा।

हापुड़ की तरफ से आने वाले वाहनों को डासना इंटरसेक्शन से इस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से होकर निकाला जाएगा।

मेरठ की तरफ से आने वाले वाहनों को दुहाई से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से होकर निकाला जाएगा।

सहारनपुर, बागपत की तरफ से आने वाले वाहनों को ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से भेजा जाएगा।

गाजियाबाद से राजधानी दिल्ली में प्रवेश करने वाले बार्डर यूपी गेट गाजीपुर बार्डर, सीमापुरी बार्डर, तुलसी निकेतन बार्डर, लोनी बार्डर व खजूरी पुस्ता मार्ग से भी सभी वाहन दिल्ली नहीं जा सकेंगे।

यातायात नहीं होगा बाधित

एडीजी यातायात बीबी पालसन ने बुधवार को जिला के यातायात पुलिस अधिकारियों के साथ रूट प्लान देखा। पुलिस उपायुक्त ने कहा कि सुरक्षा कारणों से एयरपोर्ट के आसपास के पांच हजार मकानों में रह रहे लोगों का सत्यापन किया गया है।

रूट के पास 650 दुकानदार और 150 रेहड़ी-पटरी वालों को नोटिस जारी किया गया है। उन्हें हिदायत दी गई है कि वह दुकान के बाहर किसी तरह की भीड़ न लगाए।

हिंडन एयरपोर्ट वाली सड़क का काम हुआ पूरा

छह सितंबर से राष्ट्रीय अध्यक्षों के स्टाफ की फ्लाइट हिंडन एयरपोर्ट पर आनी शुरू हो जाएगी। उनको दिल्ली ले जाने के लिए पूरी तैयारी कर ली जाएगी। वहीं हिंडन एयरपोर्ट पर बुधवार से घरेलू उड़ान सेवा भी शुरू हो जाएगी।

हिंडन एयरपोर्ट से देहरादून और लुधियाना के लिए हवाई सेवा शुरू होगी। नगर निगम के कर्मचारी दिल्ली वजीराबाद रोड पर हिंडन एयरपोर्ट से नाग द्वार तक और एलिवेटेड गोल चक्कर सड़क को चमकाने में जुटे हैं। नगर निगम ने बुधवार सुबह तक काम पूरा करने का दावा किया है।

नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि छह सितंबर से हिंडन एयरपोर्ट पर जी-20 में हिस्सा लेने वाले देशों की राष्ट्रीय अध्यक्षों का स्टाफ आना शुरू हो जाएगा। इससे पहले ही नगर निगम जी-20 रूट का काम पूरा कर देगा। आज सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रहेगी। जी-20 रूट पर सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे।

-:: यातायात एडवाइजरी ::-

यातायात पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

कृपया सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि **भारत मंडपम, प्रगति मैदान नई दिल्ली में अट्ठारवां जी– 20 शिखर सम्मेलन** प्रस्तावित है। जिसमें आमंत्रित देशों के राष्ट्राध्यक्षों/शासनाध्यक्षों एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों के द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा। जिसको सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु विभिन्न मार्गों से आकर गाजियाबाद से दिल्ली की ओर जाने वाले **भारी माल वाहनों/मध्यम माल वाहनों/हल्के माल वाहनों को दिनांक 07.09.2023 समय 19:00 बजे से दिनांक 10.09.2023 को कार्यक्रम समाप्ति तक निम्न प्रकार से डायवर्ट किया जायेगा:–**

- दिल्ली के गैर गंतव्य वाहनों का प्रवेश दिल्ली सीमा में पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित रहेगा। उपरोक्त सभी भारी माल वाहन/मध्यम माल वाहन/हल्के माल वाहन अनिवार्य रूप से ईस्टर्न पेरीफेरल का प्रयोग कर अपने गंतव्य को जायेंगे।
- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या: 91 अर्थात बुलन्दशहर की ओर से आने वाले वाहन लाल कुऑ से दिल्ली की ओर नहीं जा सकेंगे। उपरोक्त भारी माल वाहन/मध्यम माल वाहन/हल्के माल वाहन लाल कुऑ से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या: 09 से होकर ईस्टर्न पेरीफेरल का प्रयोग अपने गंतव्य को जायेंगे।
- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या: 09 अर्थात हापुड की ओर से आने वाले वाहन डासना ईस्टर्न पेरीफेरल डासना इंटरसैक्शन से आगे दिल्ली की ओर नहीं जा सकेंगे। उपरोक्त भारी माल वाहन/मध्यम माल वाहन/हल्के माल वाहन डासना इंटरसैक्शन से ईस्टर्न पेरीफेरल का प्रयोग कर अपने गंतव्य को जायेंगे।
- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या: 34 (पूर्व में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या: 58) पर मेरठ की ओर से आने वाले वाहन दुहाई से आगे गाजियाबाद की ओर नहीं जा सकेंगे। उपरोक्त भारी माल वाहन/मध्यम माल वाहन/हल्के माल वाहन दुहाई से ईस्टर्न पेरीफेरल का प्रयोग कर अपने गंतव्य को जायेंगे।
- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या: 709 बी पर सहारनपुर/बागपत की ओर से आने वाले वाहन पेरीफेरल से आगे लोनी/दिल्ली की ओर नहीं जा सकेंगे। उपरोक्त भारी माल वाहन/मध्यम माल वाहन/हल्के माल वाहन ईस्टर्न पेरीफेरल का प्रयोग कर अपने गंतव्य को जायेंगे।
- आवश्यक वस्तु सेवा अधिनियम के अन्तर्गत आवागमन करने वाले वाहन (दूध, सब्जी, फल, चिकित्सा आपूर्ति) दिल्ली की सीमा में प्रवेश कर आवागमन कर सकेंगे।
- गाजियाबाद से दिल्ली में प्रवेश करने वाले स्थानों 1–यूपी गेट गाजीपुर बॉर्डर, 2–सीमापुरी बॉर्डर, 3–तुलसी निकेतन बॉर्डर, 4–लोनी बॉर्डर, 5–खजूरी पुस्ता मार्ग से सभी प्रकार के भारी माल वाहन/मध्यम माल वाहन/हल्के माल वाहनों का प्रवेश दिल्ली में पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित रहेगा।

नोट– डायवर्जन व्यवस्था में आवश्यकतानुसार कभी भी संशोधन किया जा सकता है।

- यातायात हैल्पलाइन नम्बर :– 9643322904, 0120–2986100
- यातायात निरीक्षक द्वितीय एन0एच0–09/डासना इंटरसैक्शन :– 8929182258
- यातायात निरीक्षक चतुर्थ यूपी गेट :– 8707676770
- यातायात निरीक्षक पंचम सीमापुरी बॉर्डर :– 7007847097
- यातायात निरीक्षक षष्टम लोनी क्षेत्र :– 9219005151

अतएव किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने के लिये वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें।

अपर पुलिस उपायुक्त, यातायात
कमिश्नरेट–गाजियाबाद।

इनसाइड

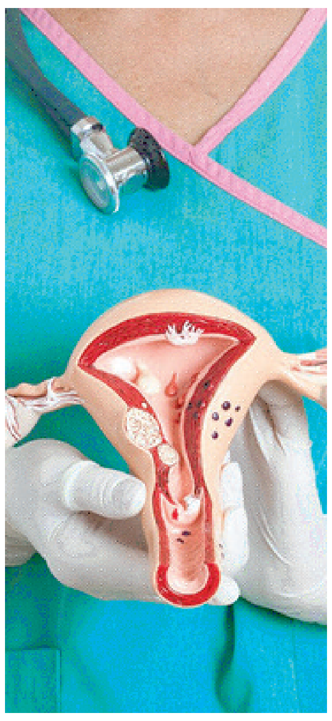

सर्वाइकल कैंसर का खतरा युवा महिलाओं को ज्यादा, अपोलो की डॉक्टर सारिका गुप्ता ने बताए बचाव के तरीके

कैंसर शरीर के किसी भी हिस्से में कोशिकाओं की असामान्य वृद्धि की वजह से हो जाता है. कैंसर कई तरह के होते हैं. इनमें से एक सर्वाइकल कैंसर (Cervical Cancer) होता है, जो महिलाओं में होने वाला कॉमन कैंसर है. दुनियाभर में हर साल बड़ी तादाद में महिलाएं महिलाएं सर्वाइकल कैंसर की वजह से अपनी जान गंवा देती हैं. चिंताजनक बात यह है कि सर्वाइकल कैंसर का खतरा कम उम्र की महिलाओं को ज्यादा होता है. आज कैंसर स्पेशलिस्ट से जानेंगे कि सर्वाइकल कैंसर क्या है, इसके क्या लक्षण होते हैं और इससे किस तरह बचा जा सकता है.

नई दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल के गायनेकोलॉजी ओन्कोलॉजी डिपार्टमेंट की सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर सारिका गुप्ता के मुताबिक सर्वाइकल कैंसर महिलाओं की बच्चेदानी के मुख में होने वाला कैंसर है. इसे बच्चेदानी के मुंह का कैंसर भी कहा जाता है. आमतौर पर 35 साल से लेकर 50 साल की उम्र वाली महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर का खतरा ज्यादा होता है. यह कैंसर दो तरह का होता है- पहला लो ग्रेड और दूसरा हाई ग्रेड. लो ग्रेड कैंसर धीरे-धीरे फैलता है, जबकि हाई ग्रेड कैंसर तेजी से फैलता है और इसमें मौत का खतरा ज्यादा होता है. ऐसे में सही वक्त पर इलाज कराना बेहद जरूरी है.

ऐसी महिलाओं को खतरा ज्यादा

डॉक्टर सारिका गुप्ता कहती हैं कि सर्वाइकल कैंसर का खतरा उन महिलाओं को ज्यादा होता है, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर हो और एचआईवी या अन्य कोई गंभीर बीमारी हो. मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, जेनिटल हाइजीन की कमी और जल्दी बच्चे होने वाली महिलाओं को इसका जोखिम ज्यादा होता है. इसके अलावा स्मोकिंग करने से भी सर्वाइकल कैंसर का खतरा बढ़ जाता है. 30 साल की उम्र के बाद महिलाओं को इससे बचने के लिए समय-समय पर स्क्रीनिंग करानी चाहिए. सर्वाइकल कैंसर का पता प्री-कैंसरस स्टेज में भी लगाया जा सकता है और सही इलाज के जरिए कैंसर से बचा भी जा सकता है.

सर्वाइकल कैंसर के लक्षण

– पार्टनर के साथ संबंध बनाने के बाद ब्लीडिंग
– पीरियड्स के बीच अनियमित माहवारी होना
– बदबूदार पानी आना या ब्लड स्ट्रीम डिस्चार्ज
– मेनोपॉज के बाद ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होना

सर्वाइकल कैंसर का ट्रीटमेंट और बचाव

डॉक्टर के अनुसार सर्वाइकल कैंसर अगर शुरुआती स्टेज में हो, तो सर्जरी के जरिए इसका इलाज किया जाता है. एडवांस स्टेज में कीमोथेरेपी की जरूरत होती है. हर मरीज की कंडीशन को देखकर ही ट्रीटमेंट किया जाता है. जितना जल्दी इसका पता लग जाए, मौत का खतरा उतना कम हो सकता है. बचाव की बात करें, तो सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए HPV का टीका लगवाएं और अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें. स्मोकिंग से दूरी बनाएं और संबंध बनाते वक्त कॉन्ट्रासेप्टिव इस्तेमाल करें. समय-समय पर गायनेकोलॉजिस्ट से मिलकर अपनी जांच करवाएं.

महिलाओं में 5 लक्षण दिखें तो हो जाएं अलर्ट

खराब मेंटल हेल्थ के होते हैं संकेत, सही वक्त पर करें सेल्फ

अत्यधिक अपराधबोध, भय, शर्म या क्रोध का होना भी मेंटल प्रॉब्लम के शुरुआती लक्षण हैं.अत्यधिक अपराधबोध, भय, शर्म या क्रोध का होना भी मेंटल प्रॉब्लम के शुरुआती लक्षण हैं.डिप्रेशन और एंग्जायटी पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक देखने को मिलती है. ये दिमागी बीमारी के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं. हकीकत यह है कि महिलाएं महीनों, सालों और कई बार तो जीवनभर इस परेशानी से जूझती हैं, जो बाद में और भी परेशानी की वजह बन जाते हैं. आज आपको बता रहे हैं कि महिलाओं में मेंटल हेल्थ के खराब होने के शुरुआती लक्षण क्या हैं.

अक्सर यह देखने को मिलता है कि महिलाएं अपने मेंटल हेल्थ को लेकर सीरियस नहीं होतीं और सालों साल डिप्रेशन और एंग्जायटी की समस्या से जूझती रहती हैं. इलाज के अभाव में समस्या और भी बढ़ जाती है और हालात कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं. आज के बिजी लाइफ स्टाइल में महिलाएं घर और दफ्तर दोनों को सम्हालती हैं और मेंटल हेल्थ से जुड़ी काफी मामलों को नजरअंदाज कर देती हैं. लेकिन अन्य बीमारियों की तरह यह समस्या भी रुकती नहीं और धीरे धीरे जीवन को कई तरह से प्रभावित करती चली जाती हैं. आइए जानते हैं कि महिलाओं में मेंटल हेल्थ की समस्या के शुरुआती लक्षण क्या हैं.

जीवन में कठिनाइयां बढ़ना- क्लीयरव्यू ट्रीटमेंट प्रोग्राम के मुताबिक कभी-कभी मानसिक बीमारी के पहले लक्षण के रूप में देखा जाता है कि महिलाओं का परफॉरमेंस एकाएक खराब होने लगता है. मसलन, खराब ग्रेड आना, काम अच्छा ना होना, अच्छी तरह से जिम्मेदारियों को ना निभा पाना, स्ट्रेस मैनेज नहीं कर पाना, पर्सनल रिलेशन में समस्या आदि. ऐसे लक्षण महिलाओं में मेंटल हेल्थ के बिगड़ने के लक्षण हो सकते हैं.

मूड और भावनाओं में बदलाव- अगर अचानक से महिला के मूड में परिवर्तन हो या मूड में उतार-चढ़ाव आए तो ये भी मानसिक बीमारियों का एक और प्राथमिक संकेत हो सकता है. मसलन, उदास रहना, उत्साह की कमी, एनर्जी और भावनाओं की कमी या उदासीनता की भावना आदि. यही नहीं, ऐसी अवस्था में अत्यधिक अपराधबोध, भय, शर्म या क्रोध का अनुभव भी कर सकता है.

संज्ञानात्मकता की कमी- संज्ञानात्मकता की कमी यानी कि चीजों को बार बार भूलना, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई या भ्रम होना आदि लक्षण मानसिक बीमारी के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं. ऐसे हालत में इंसान इंसानों को भूल सकता है और वह कहीं खोया खोया रहता है.

खतरनाक व्यवहार- मानसिक बीमारी अगर अपने शुरुआती दौर में है तो कभी-कभी ऐसी महिलाएं जोखिम भरे व्यवहार करने लगती हैं. मसलन, अत्यधिक मात्रा में पैसा खर्च करना, जोखिम भरा यौन व्यवहार करना या ड्रग्स और शराब के साथ प्रयोग करना. इस परेशानी से पीछा छुड़ाने के लिए कई बार लोग ड्रग्स या शराब की लत तक के शिकार हो जाते हैं.

हकीकत से दूर होना- कई बार महिलाएं तनाव झेलते झेलते मतिभ्रम महसूस करने लगती हैं जिसमें उन्हें लगता है कि कुछ हो रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा. ऐसा लक्षण होने पर तुरंत आप साइक्रेटिस्ट से संपर्क करें और विशेषज्ञों से मदद लें.

लक्षण दिखने कर क्या करें ?

–अगर आप कुछ ऐसा अनुभव कर ही हैं तो विशेषज्ञ की सलाह लें.
–योग और ध्यान का सहाला लें और वॉकिंग या जॉगिंग करें.
–लोगों से मिलें और क्लब आदि ज्वाइन करें.
–बिहेवियर थेरेपी की मदद लें.

प्रियंका चोपड़ा ने 30 की उम्र में अपने एग कराए थे फ्रीज़, आखिर क यों प्रचलित हो रहा यह तरीका

बॉलीवुड में एग फ्रीजिंग तकनीक काफी फेमस हो रही है. हाल ही में प्रियंका चोपड़ा ने भी इस तकनीक की मदद से बच ची को जन म दिया है. आखिर ये तकनीक क यों फेमस हो रही है और फैमिली प लानिंग में ये किस तरह लोगों की मदद कर रही है, इस बारे में सभी को कुछ बातें जान लेनी चाहिए.

प्रियंका चोपड़ा हाल ही में जाने माने अमेरिकन एक्टर फिल्ममेकर डैक्स शेफर्ड के पॉडकास्ट आर्मचेयर एक्सपर्ट के शो में अपनी पर्सनल लाइफ के कुछ जरूरी फैसलों पर चर्चा करते हुए कई बातों को खुलासा किया. इस मौके पर उन्होंने खुलकर इस बात की जानकारी दी कि उन्होंने अपनी मां की सलाह पर अपने एग्स फ्रीज करवाए थे. उन्होंने बताया कि अपने 30 वें साल में लिए गए इस निर्णय की वजह से उन्हें जीवन में कई आजादी भी मिली. प्रियंका अभी 40 साल की हैं और सिंगर एक्टर निक जोनस के साथ एक खुशहाल मैरिड लाइफ जी रही हैं. हाल ही में एग फ्रीजिंग तकनीक से उन्हें बेटी भी हुई है, जिसका नाम मालती मेरी चोपड़ा जोनस है.

आखिर क या है एग फ्रीजिंग ?

मेडिकल न्यूज टुडे के मुताबिक, एग फ्रीजिंग एक मेडिकल प्रक्रिया है जिसमें एक महिला के पास यह विकल्प होता है कि वह बच्चे पैदा करने की उम्र निकल जाने के बाद भी सेरोगेसी से अपने बच्चे को जन्म दे सकती है. दरअसल, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, महिलाओं में अंडे की क्वालिटी घटती जाती है. ऐसे में महिला बच्चे को जन्म तो देना चाहती है लेकिन सिचुएशन की वजह से फिलहाल प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, तो ऐसी महिलाओं के लिए एग फ्रीजिंग तकनीक काफी सुविधाजनक और सेफ विकल्प हो सकता है.

एक फ्रीजिंग का क्यों बढ़ रहा ट्रेंड ?

करियर और एजुकेशन प्लान में सुविधा- जो महिलाएं एडवांस या हाइयर एजुकेशन में डिग्री हासिल करना चाहती हैं या करियर की वजह से उन्हें प्रेग्नेंसी के लिए मौका नहीं मिल पा रहा, ऐसी महिलाएं युवा अवस्था में अपने भविष्य के प्लान के लिए अंडे फ्रीज करवा सकती हैं. ऐसा करने से महिलाओं के पास एक आजादी होती है कि वे अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें, अच्छा करियर बना सकें और उम्र होने पर अपना परिवार भी बढ़ा सकें.

व्यक्तिगत परिस्थितियां- जो महिलाएं बच्चे तो पैदा करना चाहती हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई परफेक्ट साथी नहीं मिला है तो वे भविष्य में उपयोग के लिए अपने अंडे को फ्रीज करा सकती हैं. समलैंगिक संबंधों में रहने वाली महिलाएं भी बाद में बच्चा पैदा करने की इच्छा होने पर ऐसा कर सकती हैं.

कैंसर पीड़ित महिलाओं के लिए विकल्प- अगर महिला कैंसर पीड़ित है तो कीमोथेरेपी और अन्य कैंसर उपचार में आमतौर पर प्रजनन क्षमता कम हो जाती है और कई बार तो प्रजनन क्षमता खत्म भी हो जाती है. ऐसे में महिला पहले ही अपने एग को फ्रीज करा सकती हैं और इलाज के बाद फैमिली प्लानिंग कर सकती हैं.

6 बदलाव, जो 40 की उम्र के बाद हर महिला झेलती है! नॉर्मल हैं ये मेंटल और फिजिकल चेंज

इस उम्र में कई शारीरिक व मानसिक बदलाव

उम्र बढ़ने के साथ ही महिलाओं के मानसिक और शारीरिक सेहत में कई बदलाव तेजी से देखने को मिलते हैं. ये बदलाव कई बार फ्रस्टेटिंग होते हैं तो कई बार दैनिक जीवन को भी प्रभावित करते हैं. यहां हम आपको बताते हैं कि 40 की उम्र के बाद किस तरह के बदलाव महिलाएं महसूस करती हैं.

उम्र बढ़ना एक नेचुरल प्रोसेस है. लेकिन जब महिलाएं 40 की उम्र में प्रवेश करती हैं तो उनके शारीरिक और मानसिक सेहत में कुछ ऐसे बदलाव आने शुरू होते हैं जिसे वह आसानी से महसूस कर पाती है और लगभग हर महिला ऐसी समस्याओं से जूझती है. कुछ महिलाएं ऐसे बदलाव से इरिटेट होने लगती हैं और कुछ निराश हताश. यह वह समय होता है जब मेनोपॉज की तरफ आप बढ़ना शुरू करती हैं. इस समय महिलाएं शारीरिक और मानसिक बदलावों की वजह से निराश और कई बार अनकंफर्टेबल भी महसूस करती हैं. लेकिन आपको बता दें इनका समाधान संभव है.

प्रिवेंट वेबसाइट में इन विषयों की एक्सपर्ट पीएचडी, लॉरा बरमन का कहना है कि महिलाएं ऐसे हालातों को चुपचाप सहती हैं जबकि उन्हें अपने डॉक्टर से इस विषय पर सलाह लेने की जरूरत होती है. यहां हम आपको बताते हैं कि 40 की उम्र के बाद किस तरह के बदलावों से महिलाएं गुजरती हैं.

40 की उम्र के बाद महिलाओं के शरीर में बदलाव

ब्रेन फॉगिंग

अगर आप चीजों को रखकर भूल जा रही हैं या आप छोटी-छोटी बातों को याद नहीं रख पा रहीं तो ये ब्रेन फॉगिंग का लक्षण हो सकता है. ऐसी समस्याओं से बचने के लिए आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें और सही सलाह लें.

ब्लडर लीक होना

अगर आप महसूस करती हैं कि छींकने या खांसने आदि से ब्लडर से कंट्रोल छूट रहा है और लीक हो रहा है तो यह समस्या भी आपके लिए मुसीबत बन सकती है. 40 प्रतिशत महिलाएं 40 की उम्र के बाद ऐसी समस्याओं से जूझती हैं.

बालों का झड़ना

बालों के झड़ने की समस्या भी ज्यादातर महिलाएं 40 की उम्र के बाद महसूस करती हैं. यह हार्मोनल बदलाव की वजह से हो सकता है. अगर आपके बाद काफी झड़ रहे हैं तो आप डर्मोटोलोजिस्ट से संपर्क करें.

फेशियल हेयर का बढ़ना

उम्र बढ़ने पर महिला के शरीर में एस्ट्रोजन लेवल कम होता है और टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाता है. इसकी वजह से चेहरे, ठोरी, उंगलियों आदि पर बाल नजर आने लगते हैं.

सफेद बाल होना

उम्र बढ़ने के साथ ही सिर के बाल ग्रे नजर आने लगते हैं.यही नहीं, शरीर के अन्य हिस्सों पर मौजूद बालों में भी सफेद बाल नजर आने लगते हैं. इसकी वजह से कई महिलाएं शर्म महसूस करने लगती हैं. जबकि यह बॉडी को बिलकुल नॉर्मल प्रोसेस है.

हॉट फ्लश अनुभव करना

80 प्रतिशत महिलाएं मेनोपॉज के वक्त हॉट फ्लश अनुभव करती हैं. यह सिलसिला 7 से 10 साल तक चल सकता है. हालांकि यह समस्या ब्लड क्लॉट, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण भी हो सकते हैं.

व्हट्सअप चैट करने में महिलाएं पुरुषों से आगे, सर्वे में खुलासा, मेंटल हेल्थ से जुड़ा है मामला

व्हाट्सएप पर चैट करने में महिलाएं पुरुषों से काफी आगे हैं. हाल ही में मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन (Mental Health Helpline) की ओर से जारी आंकड़े बताते हैं कि टेलिफोन पर कंसल्टेशन या काउंसलिंग लेने के बजाय महिलाएं व्हाट्सएप चैट (WhatsApp Chat) के माध्यम से गोपनीय तरीके से मदद लेना पसंद करती हैं.

सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स फेसबुक (Facebook), ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलिग्राम, व्हाट्सएप (WhatsApp) या अन्य किसी भी एप्लिकेशन का इस्तेमाल आज बहुत ज्यादा बढ़ गया है. चाहे किसी समस्या का समाधान ढूंढना हो, मनोरंजन करना हो, जानकारी लेनी-देनी हो या सगे-संबंधियों से बातचीत करनी हो तो लोग इन एप्स (App) का इस्तेमाल करते हैं. कभी-कभी चैट में मैसेज टाइप करते-करते उलझन सी भी महसूस की होगी लेकिन महिलाओं के मामले में ऐसा नहीं है. व्हाट्सएप पर चैट करना (WhatsApp Chatting) महिलाओं को न केवल फोन पर बात करने के मुकाबले ज्यादा आसान लगता है बल्कि कॉनफिडेंशियल भी लगता है. वे व्हाट्सएप चैट करने में पुरुषों से काफी आगे हैं. खास बात है कि ये चैट भी इस हेल्पलाइन 9999666555 नंबर पर की गई है जो एक मेंटल हेल्थ ऑर्गनाइजेशन का है.

मानसिक स्वास्थ्य संगठन वंद्रेवाला फाउंडेशन की फ्री राष्ट्रीय हेल्पलाइन के 3 महीनों के आंकड़े बताते हैं कि फाउंडेशन की हेल्पलाइन पर मेंटल इश्यूज को लेकर सलाह और परामर्श लेने वालों में युवा आबादी ने सबसे ज्यादा व्हाट्सएप का उपयोग किया है. जबकि मध्यम आयु वर्ग और उससे ऊपर के लोगों ने टेलीफोनिक बातचीत को अधिक पसंद किया.

आंकड़ों से पता चलता है कि अधिकांश युवा अपने मानसिक स्वास्थ्य की मदद के लिए व्हाट्सएप का उपयोग कर रहे हैं और इसे बेहतर मानते हैं. 18 वर्ष से कम आयु के 65 फीसदी, 18-35 आयु वर्ग के 50 फीसदी, 35-60 आयु वर्ग के 28.3% और 60 वर्ष से अधिक आयु के 8 फीसदी लोगों ने मेंटल हेल्थ के लिए व्हाट्सएप यूज किया है.

53 फीसदी महिलाएं जबकि पुरुष 42 फीसदी..

फाउंडेशन के डेटा के अनुसार लगभग 53 फीसदी महिलाएं व्हाट्सएप चैट का उपयोग करके हेल्पलाइन से संपर्क करना पसंद करती हैं, जबकि 42 फीसदी पुरुष व्हाट्सएप चैट का उपयोग करना पसंद करते हैं. वहीं बाकी मामलों में लोग टेलिफोन के द्वारा काउंसलिंग लेते हैं.

खास बात है कि व्हाट्सएप ने उस वर्ग को सबसे ज्यादा राहत दी है जो शायद कभी भी मानसिक स्वास्थ्य सहायता ऑफलाइन क्लीनिकों पर जाकर नहीं ले सकता था. खासतौर पर ऐसी महिलाएं, लड़कियां और युवक जो अपने परिवार या साथियों को बिना बताए अपने मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं पर चर्चा करना चाहते हैं वे व्हाट्सएप का इसके लिए इस्तेमाल करते हैं. वे इसे गोपनीय मानते हैं और समय की उपलब्धता के अनुसार साइलेंट तरीके से अपनी समस्याओं का समाधान हासिल कर पाते हैं.

सुसाइड के विचारों से जूझ रहे लोग

फाउंडेशन की प्रमुख और परोपकारी, प्रिया हीरानंदानी वंद्रेवाला कहती हैं, 'हमसे संपर्क करने वाले एक तिहाई लोगों ने हमें बताया कि वे मानसिक बीमारी, चिंता, अवसाद और आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं.

जी-20 की तैयारियों पर नशेडियों ने लगाया पलीता

परिवहन विशेष। एसडी सेठी।

नई दिल्ली ।राजधानी दिल्ली में होने जा रहे जी-20 शिखर सम्मेलन देश के लिए गौरव की बात है। लेकिन दूसरी ओर नशेडियों -चोरों द्वारा बेशकमती सामानों पर बेखौफ हाथ साफ कर देश की मर्यादा को पूरा ही मिट्टी में मिलाने की जुगत में है। कहने को तो दिल्ली पुलिस समेत तमाम सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर है। लेकिन नशेडियों ने पुलिस की नाक के नीचे से दिल्ली गेट चौराहे पर लगे फैंसी फव्वारों से पीतल की नोजल चुरा कर फव्वारों की धार को बेदम कर दिया है। वहीं सबसे हैरानी वाली बात है कि सौंदर्य के साथ सुंदर लाइटिंग के लिये लगाए गए खम्भों से तांबे, सिल्वर की केबल तक काटकर ले गए। इससे सडकों पर अंधेरा छा गया है। सजावट के लिए लगाई मंहगी फुलवारी, पौधे गमलों सहित चोरी किए जा रहे हैं।(आईटीपीओ) प्रगति मैदान में जी-20 सम्मिट के लिए किए जा रहे निर्माण कार्य की सामग्रियों जिनमें लोहे के सरिये , केबल समेत मंहगी टाईलों ,पर तक चोरों ने हाथ साफ कर लिया है।

इस बावत आईटीपीओ के अधिकारियों ने बाकायदा दिल्ली पुलिस कमिश्नर तक के संज्ञान में ला दिया है। अधिकारियों के मुताबिक कई बार तो (आईटीपीओ) के कर्मचारियों ने रंगेनाथ चोरों को पकड कर पुलिस के हवाले किया है। प्रगति मैदान (आईटीपीओ) के अधिकारियों ने थक-हार कर दिल्ली पुलिस से तीन शिफ्टों में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गुहार लगाई है। इसमें एक वक्त पर 60 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती है, ।कुल 180 सुरक्षा कर्मीयों को 24 घंटे की तैनाती में लगा दिया है। फिर भी चोर अवैध तरीके से एंट्री कर रहे हैं। और बैट्री,बिजली केबल, समेत कीमती निर्माण सामग्री पर हाथ साफ कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि जी- 20 की तैयारियां मार्च महीने से चल रही हैं। इसी कडी में प्रदूषण नियंत्रण के लिए दिल्ली के प्रमुख स्थानों पर वर्टिकल गार्डन बनाए गए थे। इनमें मुनीरका फ्लाई ओवर, विकास पुरी से मुकरबा चौंक फ्ला ई ओवर के नीचे बने वर्टिकल गार्डन में लगे तमाम मंहगे फूल पौधों, गमलों को चोरी कर लिया है। इसी तरह लाजवंती गार्डन में भी वर्टिकल गार्डन में लगे फैंसी गमले प्लांटों को निगरानी के अभाव में चोरी कर लिया है। अब हालत ये है कि आनन -फानन में प्रशासन को पुनः निर्माण करना पड रहा है। बता दें की राजधानी दिल्ली की ज्यादातर सडकों के बीच लगी डिवाइडर लोहे की ग्रिल तक काट कर स्मैकियों ने बेच डाली है ।पार्कों की चाहरदिवारी में लगी लोहे की ग्रिल, फैंसी लाइट समेत लोहे के खंबे , यहां तक पार्कों में लगाये गए जिम इंस्ट्रूमेंट तक उखाडकर नशेडी ले गए है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि चोरों को रंगेहाथ पकड कर पुलिस के हवाले कर तो दिया जाता है, पर पुलिस द्वारा मजबूरी मेंउन्हें छोडना पडता है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस द्वारा थानो में बंद करने के बाद पुलिस कर्मियो द्वारा नशेडियों को बाकायदा अपनी जेब से स्मैक की पुडिया तक पिलानी पडती है। बहरहाल पूरी दिल्ली नशेडियों के मकडजाल में है। जीटी करनाल रोड हाई -वे मुकुंद पुर पर लगे फुट ओवर ब्रिज के सरिये, और लिफ्ट तक उखाड कर चोरी कर ले गए। प्प्लांनिंग के तहत शासन और पुलिस को नशेडियों की संख्या में बढोतरी को रोकने के स्थाई कारगर कदम उठाने की अवश्यकता है।

सनातन विवाद पर दृढ़ता से बयान दे तथा इंडिया बनाम भारत पर अधिकृत नेता ही बोले : पीएम मोदी ने मंत्री परिषद की बैठक में कहा

नई दिल्ली : जी 20 शिखर सम्मेलन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में सभी कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और राज्य मंत्री मौजूद थे. पीएम ने जी 20 पर मंत्रियों से कुछ बातें भी की, साथ ही इस बैठक में उन्होंने मंत्रियों को दो बड़े संदेश दिए. पीएम मोदी ने राजग के मंत्रियों से कहा कि सनातन धर्म पर उदय निधि के बयान का सही से (तथ्यों के साथ) दृढ़ता से जवाब दिया जाए और उन्हें बेनकाब करें. इसी के साथ पीएम मोदी ने मंत्रियों से कहा कि वे इंडिया बनाम भारत के विवाद में बयानबाजी न करें. मतलब जिन्हें अधिकृत किया जाए केवल वही बोलें.

सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी की इन समझाइश से साफ हो गया कि सनातन धर्म पर उदय निधि के बयान को बीजेपी बड़ा मुद्दा बनाने के मूड में है.

उल्लेखनीय हैं कि जी20 शिखर सम्मेलन से पहले तीन दिन तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम बहुत व्यस्त है क्योंकि वह आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कैबिनेट बैठक के बाद बुधवार शाम जकार्ता रवाना हो गए हैं. सूत्रों ने कहा कि 8 सितंबर को पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन सहित तीन देशों के साथ महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकें करेंगे, जबकि जी 20 की बैठक 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में होगी, यानी पीएम मोदी ने अपनी अनुपस्थिति में बीजेपी के अनाधिकृत नेताओं को दोनों ज्वलंत मुद्दों पर पर रोक लगाना जरुरी समझा हैं.

बता दें कि तमिलनाडु के मुख्य मंत्री के बेटे और मंत्री उदय निधि स्टालिन ने कम्युनिस्ट पार्टी के एक कार्यक्रम जो 'सनातन उन्मूलन' के नाम से चेन्नई में एक सितंबर को आयोजित था, में कहा था, 'सनातन का बस विरोध नहीं किया जाना चाहिए, इसे समाप्त ही कर देना चाहिए. ये धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है. हम डेंगू, मलेरिया या करोना का विरोध नहीं कर सकते, हमें इसे मिटाना पड़ता है. इसी तरह हमें सनातन को भी मिटाना है.'

सनातन धर्म पर इस विवादित बयान के विडियो के वायरल होने पर बीजेपी के साथ साथ धर्म गुरुओं ने भी उदय निधि को जमकर घेरा हुआ है. उदय निधि के बहाने बीजेपी ने विपक्षी पार्टियों के गठबंधन I.N.D.I.A. पर भी सवाल उठाने शुरु कर दिए हैं.

विदित हो कि स्टालिन की पार्टी DMK भी I.N.D.I.A. गठबंधन का हिस्सा है. धर्म गुरुओं का कहना था कि धर्म के खिलाफ इस तरह के बयान नहीं दिए जाने चाहिए. वहीं बीजेपी ने इस बयान को उदय निधि द्वारा देश के 80 प्रतिशत सनातन जन के नरसंहार करने का आह्वान का आरोप लगाया.

उदय निधि के बयान पर चौतरफा हमलों के बाद कांग्रेस समेत दूसरी पार्टियों ने खुद को संयत तरीके से अलग कर लिया हैं.

हालाकि उदय निधि अपने बयान पर कायम हैं. वैसे भी उदय निधि के दादा जो तमिलनाडू के पांच बार मुख्यमंत्री रहें स्व. करुणा निधि हैं, जो सनातन धर्म के मुखर विरोधी रहें है. विदित हो कि करुणा निधि रूस के प्रखर कम्युनिस्ट नेता जोसेफ स्टालिन और तमिल नेता पेरियार से जबरजस्त प्रभावित रहें हैं. इसी कारण करुणा निधि ने स्टालिन के नाम पर अपने बेटे का नाम रखा जो वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्य मंत्री हैं और उदय निधि के पिता हैं.

इंडिया से भारत करने पर हंगामा जारी हैं

सनातन धर्म पर मचे हंगामे के बीच इंडिया बनाम भारत की बहस भी राजनितिक हलकों से लेकर देश भर के चौक चौराहों तथा सोशल मीडिया में पुरजोर जारी है.

इस बहस की शुरुआत में, जी-20 बैठक के लिए राष्ट्रपति भवन की तरफ से निमंत्रण पत्र जारी हुए थे, इसमें 9 सितंबर को राष्ट्रपति भवन में होने वाले कार्यक्रम के लिए जारी आमंत्रण पत्र में लिखा है- द प्रेसिडेंट ऑफ भारत.

वीरवार रात 12 बजे से दिल्ली बंद, सिर्फ एंबुलेंस एंट्री

परिवहन विशेष ।एसडी सेठी। भारत के लिए गौरव जी-20 सम्मिट विदेशी मेहमानों के लिए तैयार है। अब सुरक्षा के पहलुओं पर पुलिस और खुफिया अधिकारी खासे सतर्क हैं। और पहले से तय प्लान पर अमल कराने के काम में जुट गए हैं। इसी रणनीति के तहत गुरूवार रात 12 बजे से 10 सितंबर की रात12बजे तक दिल्ली जयपुर हाईवे से दिल्ली में सभी वाहनों की एंट्री बंद हो जाएगी। तय समय की पाबंदी के तहत दिल्ली गुरूग्राम के सरहौल बार्डर से किसी भी वाहन का दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। केवल फायर ब्रिगेड,एम्बुलस, और जी-20 डेलीगेट ही आ जा पाएगें। दिल्ली जाने वाला ट्रेफिक डायवर्ट कर दिया जाएगा। केवल आपात सेवा से जुडे वाहनों को ही इफको चौंक से महरौली रोड ,आर्डर दिल्ली कापी हेडा रोड की ओर डायवर्ट किया जाएगा। एयरपोर्ट जाने वाले यात्रयों को भी ओल्ड दिल्ली कारसेवा बार्डर वाले रास्ते का प्रयोग करते हुए वहां तक पहुंचना होगा। दरअसल दिल्ली ट्रेफिक पुलिस ने अपने एडवाइजरी में बताया है कि जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान इंडिया गेट,और कर्तव्य पथ पर पैदल चलने, सा इकलास चलाने,या पिकनिक की इजाजत 10 सितंबर तक किसी को नहीं है ।इस इलाके को 'नियंत्रित क्षेत्र' घोषित किया गया है ।बता दें कि जी-20शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर को राष्ट्रीय राजधानी में होना है। ट्रेफिक आयुक्त एसएस यादव के मुताबिक केवल आवश्यक सेवाओ की ऑन लाइन डिलीवरी की इजाजत है। नई दिल्ली में स्विगी, और डोमिनोज जैसी आनलाईन फूड डिलीवरी पर रोक है। उन्होंने बताया कि जी-20 पास वाले सभी मीडिया कर्मी सीधे प्रगति मैदान कार्यक्रम कवर करने के लिए पहुंचने के बजाए जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में पहले इकट्ठा होंगें। जवाहर लाल स्टेडियम से उन्हें कार्यक्रम स्थल तक ले जाया जाएगा। मीडिया वाहनों को नई दिल्ली जिला क्षेत्र में प्रवेश की सम्मेलन के दौरान इजाजत नहीं दी जाएगी। इसके लिए गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए स्वदेशी नेविगेशन ऐप 'मैपलमायइंडिया ' के इस्तेमाल की सलाह दी है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोडा ने डीएमआरसी प्रबंध निदेशक विकास कुमार को पत्र लिखकर 8 से 10 सितंबर तक सुबह 4 बजे के आसपास मैट्रो सेवाएं शुरू करने की अपील की है।

' भारत ड्रोन शक्ति 2023'की सह-मेजबानी करेंगे भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया

ड्रोन तकनीक ने दक्षता को बढ़ाते हुए, जोखिम को कम करके और क्षमता संवर्द्धन के साथ नागरिक और रक्षा क्षेत्रों में क्रांति ला दी है। भारत सैन्य और नागरिक दोनों क्षेत्रों में ड्रोन के उपयोग में वृद्धि का साक्षी बन रहा है। भारतीय वायुसेना खुफिया निगरानी और टोही कार्यों के लिए व्यापक स्तर पर रिमोट से संचालित विमानों का उपयोग कर रही है। भारत में उभरते ड्रोन डिजाइन और विकास क्षमताओं में इसका विश्वास मेहर बाबा स्वार्म ड्रोन प्रतिस्पर्धा जैसी पहलों से हुआ है। इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से स्वदेशी क्षमता का दोहन करने का प्रयास किया गया है। भविष्य में भी इस तरह की प्रतियोगिता का आयोजन करने की तैयारी जारी है ।इन मानवरहित प्लेटफार्मों का उपयोग करने में अपने समृद्ध अनुभव का लाभ लेने के लिए, भारतीय वायुसेना 'भारत ड्रोन शक्ति 2023' की सह-मेजबानी करने के लिए ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी कर रही है। इस कार्यक्रम का आयोजन 25 और 26 सितंबर 2023 को हिंडन (गाजियाबाद) में एलएएफ के एयरबेस पर किया जाएगा, जिसका भारतीय ड्रोन उद्योग द्वारा लाइव हवाई प्रदर्शन किया जाएगा।'भारत ड्रोन शक्ति 2023' भारतीय ड्रोन उद्योग की पूरी क्षमता के साथ 50 से अधिक लाइव हवाई प्रदर्शनों की मेजबानी करेगा, जिसमें सर्वेक्षण ड्रोन, कृषि ड्रोन, आग दमन ड्रोन, सामरिक निगरानी ड्रोन, हेवी-लिफ्ट लॉजिस्टिक्स ड्रोन, लोटरिंग मूनिशन सिस्टम का प्रदर्शन, ड्रोन समूह और काउंटर-ड्रोन के साथ-साथ 75 से अधिक ड्रोन स्टार्ट-अप और कॉरपोरेट्स की भागीदारी होगी ।इस कार्यक्रम में केंद्र सरकार, राज्य सरकार विभागों, सार्वजनिक और निजी उद्योगों, सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, मित्र देशों के प्रतिनिधियों, शिक्षाविदों और छात्रों एवं ड्रोन के प्रति जिज्ञासा रखने वाले लगभग 5,000 लोगों के उपस्थित होने की उम्मीद है। इस आयोजन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि 'भारत ड्रोन शक्ति 2023' 2030 तक वैश्विक ड्रोन केंद्र बनने की भारत की प्रतिबद्धता को बढ़ावा देगा।

– दिल्ली ट्रैफिक पुलिस सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म के जरिए लाइव अपडेट भी देगी।

जी-20 एरिया तीन हिस्सों में बांटा, जोन के हिसाब से चलेगा ट्रैफिक; जानिए पूरा

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म के जरिए लाइव अपडेट भी देगी ।सार्वजनिक सुरक्षा और आम जनता की सुविधा के हित में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर), विशेषकर नई दिल्ली जिले और इसके आसपास के क्षेत्रों में वाहनों की आवाजाही पर विस्तृत नियम लागू होंगे।

राजधानी दिल्ली जी-20 समिट के लिए पूरी तरह से तैयार है। कल यानी 8 सितंबर से भारत में जी20 समिट की शुरुआत होने जा रही है। नई दिल्ली क्षेत्र में गुरुवार रात 12 बजे से प्रतिबंध लागू हो जाएगा। 10 सितंबर की रात 12 बजे तक प्रतिबंध लागू रहेंगे। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म के जरिए लाइव अपडेट भी देगी।

- जी-20 सम्मेलन के दौरान सुचारू संचालन के लिए मोबाइल में मैप माई इंडिया एप लोड करे। इस एप से पता लग जाएगा कि मार्ग में कहां रूकावट है, कौनसा रास्ता खुला हुआ है, कहां जाम लग रहा है और वीआईपी के लिए कहां रूट लगा हुआ है। ये बंद रास्तों को छोड़कर आपको आपके गंतव्य तक पहुंचा देगी।

- दिल्ली ट्रैफिक पुलिस सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म के जरिए लाइव अपडेट भी देगी।

- सार्वजनिक सुरक्षा और आम जनता की सुविधा के हित में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.आर), विशेषकर नई दिल्ली जिले और इसके आसपास के क्षेत्रों में वाहनों की आवाजाही पर विस्तृत नियम लागू होंगे।

- सभी आवश्यक सेवाओं को बाधा रहित आवाजाही और उनके गंतव्य तक पहुंचने का रास्ता प्रदान किया जायेगा । चिकित्सा आपातकालीन वाहनों के लिए पूरी दिल्ली में परेशानी मुक्त आवाजाही सुनिश्चित की जाएगी । वैकल्पिक मार्गों और परिवहन साधनों के माध्यम से आम जनता की आवाजाही को भी सुगम बनाया जाएगा।

- जिन वाहन को सिर्फ दिल्ली से गुजरना है उन्हें दिल्ली में प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। ऐसे वाहनों को ईस्टर्न एवं वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और अन्य वैकल्पिक मार्गों पर अनिवार्य रूप से मोड़ा जाएगा।

- सभी तरह के माल वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, आवश्यक वस्तुएं जैसे दूध, सब्जियां, फल, चिकित्सा आपूर्ति आदि ले जाने वाले मालवाहक वाहनों को वैध नो एन्ट्री परमिशन के साथ दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी।

- अंतर्राज्यीय बसों को भी दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। मगर दिल्ली में रिंग रोड से आगे नहीं जा सकेंगी।

- दिल्ली में पहले से मौजूद बसें, रिंग रोड और रिंग रोड से आगे दिल्ली की सीमाओं की ओर के चल सकेंगी। इन बसों को दिल्ली से बाहर निकलने की अनुमति होगी।

-दिल्ली में पहले से मौजूद सभी प्रकार के वाणिज्यिक वाहनों और बसों सहित सामान्य यातायात को रिंग रोड और रिंग रोड से आगे दिल्ली की सीमाओं की ओर जाने की अनुमति दी जाएगी।

- ऑटो और टैक्सियों को नई दिल्ली जिले के बाहर सड़क नेटवर्क पर चलने की अनुमति दी जाएगी । हालांकि, नई दिल्ली जिले के स्थानीय निवासियों और नई दिल्ली जिले की सीमा के अंदर स्थित होटलों में, वैध बुकिंग वाले पर्यटकों को ले जाने वाली टैक्सियों को नई दिल्ली जिले की सीमा के चलने की अनुमति दी जाएगी।

- हवाई अड्डे, नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशनों तक यात्रियों की आवाजाही की अनुमति रहेगी ।हालांकि, ऐसे यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे सुझाए गए वैकल्पिक मार्गों को ही चुनें और अपनी यात्रा के लिए पर्याप्त समय से चलें।

- नई दिल्ली जिले में प्रवेश करने वाले यातायात की आवाजाही को नियंत्रित किया जाएगा।

- दिल्ली पुलिस ने एम्बुलेंस सहायता नियंत्रण कक्ष का हेल्पलाइन नंबर 6828400604/112 जारी किया है।

- स्थानीय निवासियों और अधिकृत वाहनों को नई दिल्ली जिले के भीतर आने–जाने के लिए सुविधा प्रदत्त की जायगी। नई दिल्ली जिले में होटलों, अस्पतालों और अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के लिए हाउसकीपिंग, खानपान, अपशिष्ट प्रबंधन आदि से जुड़े वाहनों को सत्यापन के बाद प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। स्थानीय निवासियों, अधिकृत वाहनों और उपरोक्त आवश्यक सेवा प्रदाताओं को अपनी पहचान साबित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज साथ में रखने होंगे।

- मालवाहक वाहनों और बसों को छोड़कर सामान्य यातायात को रजोकरी सीमा से दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके अलावा, इस यातायात को अनिवार्य रूप से एनएच–48 से राव तुला राम मार्ग–ओलोफ पाल्मे मार्ग पर परावर्तित किया जाएगा। एनएच– 48 पर धौला कुआँ की ओर किसी भी वाहन की आवाजाही की अनुमति नहीं होगी।

- 7 और 8 सितंबर की मध्यरात्रि को 12 बजे से 10 अगस्त को 12 बजे तक सभी प्रकार के माल वाहन, वाणिज्यिक वाहन, अंतरराज्यीय बसें और स्थानीय सिटी बसें जैसे डीटीसी बसें और दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम बसों को मथुरा रोड (आश्रम चौक से आगे) भैरों रोड, पुराना किला रोड और प्रगति मैदान सुरंग के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

यातायात के लिए तीन जोन बनाए गए-

कंट्रोल एरिया-1

नई दिल्ली जिले के संपूर्ण क्षेत्र को दिनांक 8 सितंबर के 5 बजे से 10 सितंबर 12 बजे तक कंट्रोल एरिया-1 बनाया गया है। हालांकि, स्थानीय निवासियों, अधिकृत वाहनों और आपातकालीन वाहनों को नई दिल्ली जिले की सड़कों पर यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी।

विनियमित क्षेत्र–

रिंग रोड (महात्मा गांधी मार्ग) के अंदर के पूरे क्षेत्र को दिनांक 8 सितंबर 5 बजे से 10 सितंबर 12 बजे तक बजे तक विनियमित क्षेत्र बनाया गया है। केवल स्थानीय निवासियों, अधिकृत वाहनों, आपातकालीन वाहनों और हवाई अड्डे, पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों की ओर जाने वाले यात्रियों के वाहनों को रिंग रोड से आगे नई दिल्ली जिले की तरफ सड़कों पर जाने की अनुमति होगी।

कंट्रोल एरिया-2

निम्नलिखित सड़कों और जंक्शनों को 9 सितंबर व 10 सितंबर की रात 12 बजे से 10 सितंबर को 14 बजे तक कंट्रोल एरिया-2 बनाया गया है। डब्ल्यू– प्वाइंट, ए– प्वाइंट, डीडीयू मार्ग, विकास मार्ग (नोएडा लिंक रोड– पुस्ता रोड तक), बहादुर शाह जफर मार्ग, दिल्ली गेट, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (राजघाट से गुरु नानक चौक तक), चमन लाल मार्ग (गुरु नानक से) चौक से तुर्कमान गेट), आसफ अली रोड (तुर्कमान गेट से बी.एस.जेड. मार्ग तक), महाराजा रणजीत सिंह मार्ग (बाराखंभा– टॉल्स्टॉय क्रॉसिंग से चमन लाल मार्ग पर गुरु नानक चौक तक), महात्मा गांधी मार्ग (दिल्ली– मेरठ एक्सप्रेसवे टी– प्वाइंट से) कश्मीरी गेट तक), आईपी फ्लाईओवर, शांति वन चौक, हनुमान सेतु, आई.एस.बी.टी. कश्मीरी गेट और सलीमगढ़ बाईपास। 10 सितंबर को 5 बजे से लेकर 13 बजे तक इन मार्गो पर ट्रैफिक लगभग बंद रहेगा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, अजमेरी गेट की ओर से,पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोड की ओर से, शांति वन चौक, गीता कॉलोनी की ओर से,आईटीओ, विकास मार्ग की ओर से,राजघाट चौक, जवाहर लाल नेहरू (जेएलएन) मार्ग की ओर से और गुरु नानक चौक, मिंटो रोड की ओर से।

बस सेवाएं

- अंतरराज्यीय बसों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी और उनका समापन गंतव्य रिंग रोड पर होगा ।

- गाजीपुर बॉर्डर से दिल्ली आने वाली बसें- आई.एस.बी.टी सराय काले खां खत्म हो जाएंगी।

- अप्सरा बॉर्डर -आई.एस.बी.टी कश्मीरी गेट

- चिल्ला बॉर्डर-आई.एस.बी.टी सराय काले खां

- बदरपुर बॉर्डर- आश्रम चौक

- टीकरी बॉर्डर- पीरागढ़ी चौक

- सिंघू बॉर्डर-मुकरबा चौक

मेट्रो सेवाएं

सभी मेट्रो स्टेशनों पर यात्रियों के लिए मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध रहेगी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर दिनांक नौ सितंबर को सुबह 5 बजे से 10 सितंबर को रात 11:00 बजे तक मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध नहीं होगी।

ट्रैफिक पुलिस ने जारी की हेल्पलाइन

दिल्ली पुलिस ने आम जनता और वाहन चालकों को सलाह दी है कि वे धैर्य रखें, यातायात नियमों और सड़क अनुशासन का पालन करें और सभी चौराहों पर तैनात यातायात कर्मियों के निर्देशों का पालन करें और दिल्ली यातायात पुलिस की वेबसाइट https://traffic.delhipolice.gov.in, फेसबुक पेज https://www.facebook.com/dtptraffic, ट्विटर हैंडल https://twitter.com/dtptraffic, इंस्टाग्राम पेज https://www.instagram.com/dtptraffic, व्हाट्सएप नंबर 8750871493 और हेल्पलाइन नंबर 1095/011–25844444 के माध्यम से अद्यतन (अपडेट) रहें।

गाजियाबाद: रोक लगाने के बाद भी चल रहा हिंडन एयरपोर्ट के पास निर्माण कार्य, GDA ने G20 की बैठक चलते लगाई थी रोक

परिवहन विशेष न्यूज

हिंडन एयरपोर्ट के पास निर्माण कार्य पर रोक लगाने के बाद भी लोग बाज नहीं आ रहे हैं। एयरपोर्ट की दीवार से आठ से 12 मीटर की दूरी पर मकानों का निर्माण कार्य चल रहा है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने जी-20 के दौरान एयरपोर्ट के पास चल रहे मकानों के निर्माण करने पर रोक लगा दी थी।

गाजियाबाद/ साहिबाबाद। हिंडन एयरपोर्ट के पास निर्माण कार्य पर रोक लगाने के बाद भी लोग बाज नहीं आ रहे हैं। एयरपोर्ट की दीवार से आठ से 12 मीटर की दूरी पर मकानों का निर्माण कार्य चल रहा है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने जी-20 के दौरान एयरपोर्ट के पास चल रहे मकानों के निर्माण करने पर रोक लगा दी थी।

कुछ मकानों की छत की खिड़की हिंडन एयरपोर्ट की ओर खुल रही थी। जीडीए ने इन मकानों की खिड़की को बंद करा दिया था। जिन मकानों में दूसरी और तीसरी मंजिल का निर्माण कार्य चल रहा था उसे भी बंद करने के लिए कहा था।

मीडिया की टीम बृहस्पतिवार को एयरपोर्ट के पास की कॉलोनी की हिंडन एयरपोर्ट से सटी गलियों में पहुंची। कुछ मकान एयरपोर्ट की दीवार से आठ से 12 मीटर की दूरी पर बने हैं। कई मकानों में दीसरी और तीसरी मंजिल पर निर्माण कार्य होता हुआ पाया। मकान मालिक मौके पर नहीं मिले।

वहां काम कर रहे कामगारों ने दैनिक जागरा की टीम से पूछा कि जी-20 की वजह से कब तक निर्माण कार्य पर रोक रहेगी ? उन्हें मकान मालिक ने इसे बारे में नहीं बताया है।

उन्होंने बताया कि कुछ अधिकारी आए थे और तीन-चार दिन के लिए निर्माण कार्य को बंद रखने के लिए बोलकर गए थे। मकान मालिक निर्माण कार्य करा रहा है। इसी तरह एयरपोर्ट के पास अन्य जगह पर भी मकानों निर्माण होता हुआ नजर आया।

अतिक्रमण को हटाया गया

नगर निगम की ओर से दुकानदारों को नोटिस दिया गया है कि वह अपना सामान सड़क तक न फैलाए। दुकान के आगे कोई भी ठेली-पटरी वाला नहीं होना चाहिए। पसोंडा, सिकंदरपुर, गरिमा गार्डन, शालीमार गार्डन, राजेंद्र नगर और करहैड़ा में ठेली-पटरी वालों को हटाया गया है।

अब रोड पर एक भी ठेली-पटरी वाला नहीं दिखाई दे रहा हैं। जी-20 सम्मेलन के बाद ही लोग ठेली-पटरी लगा सकेंगे।

इस बारे में प्रभारी मुख्य अभियंता, मानवेंद्रे सिंह ने कहा कि मकानों निर्माण और खिड़की बंद आदि का काम प्रवर्तन दल देख रहा है। इसमें वहीं कुछ बता सकते हैं।

G20 Summit से पहले दिल्ली-एनसीआर का मौसम हुआ सुहावना, गुरुग्राम में झमाझम बारिश

राष्ट्रीय राजधानी में उमस भरी गर्मी से लोग बेहाल हैं लेकिन जी-20 सम्मेलन से पहले राष्ट्रीय राजधानी का मौसम थोड़ा करवट बदल ली है और कई इलाकों में मौसम सुहावना हो गया है। गुरुवार दोपहर को दिल्ली से सटे हुए गुरुग्राम में हुई झमाझम बारिश से आसपास का मौसम खुशनुमा हो गया है। बारिश के बाद दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेस-वे पर लंबा जाम लग गया है।

गुरुग्राम। राष्ट्रीय राजधानी में उमस भरी गर्मी से लोग बेहाल हैं, लेकिन जी-20 सम्मेलन से पहले राष्ट्रीय राजधानी का मौसम थोड़ा करवट बदल ली है और कई इलाकों में मौसम सुहावना हो गया है।

गुरुवार दोपहर को दिल्ली से सटे हुए गुरुग्राम में हुई झमाझम बारिश से आसपास का मौसम खुशनुमा हो गया है। वहीं, गुरुग्राम में गुरुवार को हुई तेज बारिश के बाद इफको चौक के पास स्थित दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेस-वे पर लंबा जाम लग गया है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

दुल्हन की तरह सजा गाजियाबाद का एलिवेटेड रोड; अब ट्रांस हिंडन को मेहमानों का इंतजार

परिवहन विशेष न्यूज

जी-20 रूट पर काम पूरा कर लिया गया है। अब अधिकारियों को जी-20 सम्मेलन में भाग लेने के लिए आ रहे मेहमानों का इंतजार है। एलिवेटेड रोड को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। बृहस्पतिवार को इस रूट पर किसी स्थान पर काम होता नजर नहीं आया। पीडब्ल्यूडी की दिल्ली सीमा से एयरफोर्स स्टेशन गोल चक्कर तक दो लेन का पुनर्निर्माण काम पूर कर लिया है।

गाजियाबाद/साहिबाबाद। जी-20 रूट पर काम पूरा कर लिया गया है। अब अधिकारियों को जी-20 सम्मेलन में भाग लेने के लिए आ रहे मेहमानों का इंतजार है। एलिवेटेड रोड को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। बृहस्पतिवार को इस रूट पर किसी स्थान पर काम होता नजर नहीं आया।

हिंडन एयरपोर्ट से लेकर यूपी गेट तक जी-20 रूट पर पौधे रोपित किए गए हैं और फूलदार गमले रखे गए हैं। एलिवेटेड रोड पर लगी तिरंगा लाइट लोगों को आकर्षित कर रही हैं। आशंका है कि रात में भी विदेशी मेहमानों की फ्लाइट आ सकती है। ऐसे में जगह-जगह लगी रंगीन लाइट लगाई गई है।

पीडब्ल्यूडी का अधूरा पड़ा सड़क बनाने का काम पूरा कर लिया है। पीडब्ल्यूडी की दिल्ली सीमा से एयरफोर्स स्टेशन गोल चक्कर तक तीन लेन की सड़क है। विभाग ने केवल दो लेन का ही पुनर्निर्माण किया है। डिवाइडर पर रंगाई तो करा दी है लेकिन पौधे नये सिरे नहीं लगाए गए हैं।

टाइल्स लगाने का काम भी हुआ पूरा

सड़क के किनारे कई जगह टाइल्स लगाने का काम चल रहा था। नगर निगम ने टाइल्स लगाने का काम पूरा कर दिया है। इस रूट के पास के नालों को साफ कर दिया गया है। सड़क के किनारे लगातार पानी से छिड़काव किया जा रहा है। रात में भी अधिकारी रूट की देखदेख करेंगे।

फ्लाइट आने की सूचना किसी के पास नहीं

पीडब्ल्यूडी और नगर निगम के अधिकारियों को फ्लाइट आने की जानकारी नहीं दी गई है। उन्हें केवल समय पर काम पूरा करने का निर्देश दिया गया था।

नगर निगम के मुख्य अभियंता एनके चौधरी ने बताया कि नगर निगम का काम पूरा हो गया है। अब केवल मेहमानों के आने का इंतजार है। नगर निगम के कर्मचारी पौधों में पानी लगाने, लाइट खराब होने, होर्डिंग हटाने आदि पर नजर रख रहे हैं। यदि कुछ खराब होता है तो उसे तुरंत ही ठीक किया जाएगा।

रेवड़ियां बांटने की राजनीति देश के लोकतंत्र का बड़ा नुकसान कर रही है

ललित गर्ग

यथार्थ में देखा जाए तो जनतंत्र अर्थतंत्र बनकर रह जाता है, जिसके पास जितना अधिक पैसा होगा, वह उतने ही अधिक वोट खरीद सकेगा। सभी दल पैसे के दम पर चुनाव जीतना चाहते हैं, जनता से जुड़े मुद्दों एवं समस्याओं के समाधान के नाम पर नहीं।

लोकसभा एवं पांच प्रांतों में विधानसभा चुनाव सन्निकट है, जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, हैसियत से आगे निकलकर राजनीतिक दल जनता को मुफ्त की रेवड़ियां एवं सुविधाएं देने के लिए वादों का पिटारा खोलते जा रहे हैं, चुनाव सुधार की दिशा में सार्थक कदम इन चुनावों में भी उठते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिताऊ उम्मीदवार अब भी राजनीतिक दलों की चुनाव प्रक्रिया पर हावी है, धनबल एवं बाहुबल का ही वर्चस्व एक बार फिर देखने को मिले, तो कोई आश्चर्य नहीं है। योग्यता और उपलब्धियां एक बार फिर हवा होगी। प्रश्न है कि चुनाव सुधार की प्रक्रिया कब मजबूती से आगे बढ़ेगी, चुनाव जनतंत्र की जीवनी शक्ति है। यह राष्ट्रीय चरित्र का प्रतिबिम्ब होता है। जनतंत्र के स्वस्थ मूल्यों को बनाए रखने के लिए चुनाव की स्वस्थता, पारदर्शिता और उसकी शुद्धि अनिवार्य है। चुनाव की प्रक्रिया गलत होने पर लोकतंत्र की जड़ें खोखली होती चली जाती हैं।

चुनाव प्रक्रिया महंगी एवं धन के वर्चस्व वाली होने से विसंगतिपूर्ण एवं लोकतंत्र की आत्मा का हनन करने वाली हो जाती है। करोड़ों रुपए का खर्चीला चुनाव, अच्छे लोगों के लिये जनप्रतिनिधि बनने का रास्ता बन्द करता है और धनबल एवं धंधेबाजों के लिये रास्ता खोलता है। हाल के वर्षों में चुनाव सुधार की दिशा में जितने भी कदम उठे हैं, उनमें राजनीतिक दलों की बजाय सर्वोच्च न्यायालय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका रही है या फिर चुनाव आयोग की। लोकप्रतिनिधित्व कानून 1951 के तहत चुनाव आयोग भारत में चुनाव कराता है। साल 1990 में जब टीएन शेषन देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाए गए तो उन्होंने चुनाव सुधारों की दिशा में वे कदम उठाए जो असंभव समझे जाते थे। शेषन चुनाव-सुधार के प्रेरक बने एवं उन्होंने क्रांतिकारी कदम उठाते हुए पहली बार देश को अहसास कराया कि चुनाव आयोग नामक कोई दमदार संस्था भी होती है, जो चाहे तो बंदूकों के दम पर बूथ लूटने वाले आपराधिक तत्वों पर लगाम लगा सकती है। तभी पता चला कि चुनावी प्रशासन कितना कठोर और अनुशासनबद्ध हो सकता है।

शेषन के बाद चुनाव आयोग सक्रिय हुआ है, लेकिन शेषन जैसे प्रभावी कदम उठाने की कमी अब भी दिखाई दे रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अरविन्द केजरीवाल, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान एवं राजस्थान में अशोक गहलोत सरकारों ने मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की झड़ी लगा रखी है। धनबल एवं बाहुबल के बाद इन वर्षों में सर्वाधिक मुक्त सुविधाएं देने की घोषणाएं समूची लोकतांत्रिक प्रणाली को दूषित करने का सबब बन रही है। इस तरह की बुराई एवं विकृति को देखकर आंख मूंदना या कानों में अंगुलियां डालना जनता की राष्ट्र के प्रति उदासीनता का द्योतक है, जरूरत इसके विरोध में व्यापक जनचेतना को जगाने की है। यह समस्या या विकृति किसी एक प्रांत की नहीं, बल्कि समूचे राष्ट्र की लोकतांत्रिक समस्या है।

साल 2015 में चुनाव आयोग ने अपनी चुनावी गाइड लाइन में कहा था कि राजनीतिक दल चुनावी मैदान में उतरते वक्त मतदाताओं से जो वादे करते हैं, उन्हें यह भी बताना होगा कि किस स्रोत से सत्ता में आने के बाद उन्हें पूरा करेंगे। ऐसी गाइन लाइन का पालन कहां होता है ? आम चुनाव एवं पांच राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनावों के मद्देनजर चुनाव आयोग को चाहिए कि कम से कम इस बार अपने दिशा-निर्देशों को सख्ती से लागू करे। चूंकि राजनीति में सेवा अब ज्यादातर दिखावटी हो गई है, मकसद व्यक्तिगत और दलगत दोनों स्तरों पर सिर्फ सत्ता प्राप्ति ही रह गया है। मुफ्त की रेवड़ियां बांटने या अतिश्योक्तिपूर्ण सुविधाओं की घोषणाएं करने के पीछे भी मकसद यही है। इस पूरी प्रक्रिया में अंततः नुकसान जनता को ही होता है। तरह-तरह के नये टैक्स और महंगाई के बोझ से आखिर जनता ही दबती है। अब जरूरी हो गया है कि साल 2015 के अपने ही दिशा-निर्देश को कड़ाई से लागू करने की दिशा में चुनाव आयोग आगे बढ़े। राजनीतिक दल जनता को बताएं कि जो वादे वे कर रहे हैं उन्हें किस स्रोत से पूरा करेंगे। तब मतदाता भी फायदा या नुकसान समझ पाएगा। तब शायद वोट देते वक्त वह अपने विवेक पर भरोसा करने की दिशा में भी आगे बढ़ना शुरू कर सकेगा। चुनावों में धनबल का बढ़ता प्रयोग एवं मुफ्त रेवड़ियां बांटने का दूषित एवं पूर्वाग्रहपूर्ण प्रचलन चिन्ता का सबब होना चाहिए। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, चौपट काम-धंधे एवं जीवन संकट के समाधान में क्या पांच राज्यों के विधानसभा एवं अगले वर्ष होने वाले आम चुनाव कोई आदर्श प्रस्तुत कर पायेंगे ? इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है, जो लोग चुनाव जीतने के लिए इतना अधिक खर्च कर सकते हैं तो वे जीतने के बाद क्या करेंगे, पहले अपनी जेब को भरेंगे, आम जनता पर आर्थिक दबाव बनायेंगे। और मुख्य बात तो यह है कि यह सब पैसा आता कहां से है ? कौन देता है इतने रुपये ? धनाढ्य अपनी तिजोरियां तो खोलते ही हैं, कई कम्पनियां हैं जो इन सभी चुनावी दलों एवं उम्मीदवारों को पैसे देती हैं, चंदे के रूप में। चन्दा के नाम पर यदि किसी बड़ी कम्पनी ने धन दिया है तो वह सरकार की नीतियों में हेरफेर करवा कर लगाये गये धन से कई गुणा वसूल लेती है। इसीलिये वर्तमान की भारतीय राजनीति में धनबल का प्रयोग चुनाव में बड़ी चुनौती है।

यथार्थ में देखा जाए तो जनतंत्र अर्थतंत्र बनकर रह जाता है, जिसके पास जितना अधिक पैसा होगा, वह उतने ही अधिक वोट खरीद सकेगा। सभी दल पैसे के दम पर चुनाव जीतना चाहते हैं, जनता से जुड़े मुद्दों एवं समस्याओं के समाधान के नाम पर नहीं। कोई भी ईमानदारी और सेवाभाव के साथ चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। राजनीति के खिलाड़ी सत्ता की दौड़ में इतने व्यस्त है कि उनके लिए विकास, जनसेवा, सुरक्षा, महामारियां, आतंकवाद, बेरोजगारी, महंगाई की बात करना व्यर्थ हो गया है। सभी पार्टियां जनता को गुमराह करती नजर आती हैं। सभी पार्टियां नोट के बदले वोट चाहती हैं। राजनीति अब एक व्यवसाय बन गई है। सभी जीवन मूल्य बिखर गए हैं, धन तथा व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए सत्ता का अर्जन सर्वोच्च लक्ष्य बन गया है, बात चाहें विधानसभा चुनावों की हो या लोकसभा चुनाव की। लेकिन इस तरह लोकतंत्र की आत्मा का ही हनन होता है, इस सबसे उन्नत एवं आदर्श शासन प्रणाली पर अनेक प्रश्नचिन्ह खड़े होते हैं।

आगामी चुनावों की सबसे बड़ी विडम्बना एवं विसंगति भी जो सामने आने वाली है वह यह है कि चुनाव आर्थिक विषमता की खाई को पाटने की बजाय बढ़ाने वाले साबित होंगे। क्योंकि ये चुनाव अब तक के सर्वाधिक खर्चीले होने जा रहे हैं, इन चुनावों से पहले जिस तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं या देने की घोषणाएं की जा रही हैं, वे नयी बनने वाली सरकारों के लिये बड़ी चुनौती होगी। संभव है ऐसी अतिश्योक्तिपूर्ण घोषणाएं एवं मुफ्त रेवड़ियां बांटने वाले दलों की सरकारें बन भी जाये। लेकिन प्रश्न है कि वे इन आश्वासनों एवं घोषणाओं को पूरा करने के लिये धन कहां से लायेंगे ? जैसा कि 'मुफ्त' के वादे के साथ पंजाब में आम आदमी पार्टी सत्तारुढ़ तो हो गई, पर अब उसके बोर्डों और निगमों को पैसे की कमी से जूझना पड़ रहा है। यही हाल दिल्ली का भी है। दिल्ली परिवहन निगम में सालों से नई बसें नहीं आईं, सड़कों का बदहाल है और निगम करीब पैंतालीस हजार करोड़ के घाटे में है। दिल्ली जल बोर्ड भी सत्तर हजार करोड़ के घाटे में है। पंजाब में पुरानी पेंशन योजना लागू करना भी कठिन हो गया है। जबकि सत्ताधारी दल ने चुनाव लड़ते वक्त इसका वादा किया था। हिमाचल में भी पुरानी पेंशन और महिलाओं को मासिक भत्ता देने का वादा करके कांग्रेस सत्ता में आई। पर बढ़ते आर्थिक बोझ के चलते वादे लागू करना मुश्किल पड़ता जा रहा है। मई में कर्नाटक में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पांच गारंटियों का वादा करके जीत गई। पर अब गारंटी पूरा करना कठिन होता जा रहा है। सामान्य विकास के लिए धन की कमी पड़ती है तो इन सुनहरे सपने दिखाने वाली घोषणाओं को आकार देने एवं पूरा करने के लिये धन कहां से आयेगा ? आखिर कब तक चुनाव इस तरह की विसंगतियों पर सवार होता रहेगा ?

Tata Motors अगले 3 महीनों के अंदर 5 नई SUVs कर रही है लॉन्च, लिस्ट में 2 इलेक्ट्रिक कार भी शामिल

भारतीय बाजार के अंदर अपनी 5 नई कारों को लॉन्च करने के लिए तैयार है। कंपनी ने इनमें से 2 कारों को पेश भी कर दिया है। 14 सितंबर को टाटा मोटर्स अपडेटेड नेक्सन और नेक्सन ईवी की कीमतों की घोषणा करेगी। इसके बाद फेसलिफ्टेड टाटा हैरियर और टाटा सफारी को आने वाले महीनों में पेश किया जाएगा।

नई दिल्ली। देश की पॉपुलर कार निर्माता कंपनी Tata Motors भारतीय बाजार के अंदर अपनी 5 नई कारों को लॉन्च करने के लिए तैयार है। कंपनी ने इनमें से 2 कारों को पेश भी कर दिया है। बाकी 3 कारों को अगले 3 महीनों के अंदर लॉन्च किए जाना है। आइए, इस लेख में जल्द ही लॉन्च होने वाले नेक्सन फेसलिफ्ट और नेक्सॉन ईवी फेसलिफ्ट के साथ-साथ अपडेटेड हैरियर, सफारी और बिल्कुल नई पंच ईवी के बारे में जान लेते हैं।

Tata Nexon Facelift और Nexon EV Facelift

14 सितंबर को टाटा मोटर्स अपडेटेड नेक्सन और नेक्सन ईवी की कीमतों की घोषणा करेगी। नेक्सन फेसलिफ्ट का खुलासा कुछ दिन पहले कर दिया गया है और नई नेक्सन ईवी आज यानी 7 सितंबर को लॉन्च होगी। दोनों कॉम्पैक्ट एसयूवी की कीमतें 14 सितंबर को सामने आएंगी। इन दोनों ही SUVs में बहुत कुछ समानता है, क्योंकि ये कर्व कॉन्सेप्ट से प्रेरित हैं।

Tata Harrier Facelift और Safari Facelift

फेसलिफ्टेड टाटा हैरियर और सफारी को आने वाले महीनों में पेश किया जाएगा और इसकी डिजाइन काफी हद तक हैरियर ईवी कॉन्सेप्ट से प्रभावित होगी। इस साल की शुरुआत में 2023 ऑटो एक्सपो में इसका अनावरण किया गया था। अपडेटेड एसयूवी के फ्रंट फेशिया में संशोधन होंगे और इंटीरियर में भी कई नए फीचर्स और तकनीक शामिल होंगी। दोनों को 2.0L डीजल इंजन द्वारा संचालित किया जाना जारी रहेगा।

Tata Punch EV

Tata Punch EV को भारत में अक्टूबर 2023 में पेश किया जाएगा और यह दूसरी पीढ़ी के ईवी आर्किटेक्चर के साथ ALFA (एजाइल लाइट फ्लेक्सिबल एडवांस्ड) प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी। इसमें लिप्टन तकनीक और एक लिक्विड-कूल्ड बैटरी पैक और स्थायी चुंबक सिंक्रोनस मोटर की सुविधा होगी।

उम्मीद है कि इसकी ड्राइविंग रेंज 350 किमी के आसपास होगी और ये टियागो ईवी और टिगोर ईवी के ऊपर स्थित होगी। जासूसी तस्वीरों से पता चलता है कि इसमें नया टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, चारों पहियों पर डिस्क ब्रेक, फ्रंट बंपर पर चार्जिंग सॉकेट, 10.25 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल सकता है।

माई ईवी स्टोर ने लॉन्च किया IME रैपिड इलेक्ट्रिक स्कूटर, सिंगल चार्ज पर दौड़ेगी 300 किलोमीटर

MY EV स्टोर ने ग्राहकों के लिए आकर्षक, आसान और सिंपल फाइनेंस स्कीम के लिए कोटक महिंद्रा, श्रीराम फाइनेंस और मणप्पुरम फाइनेंस सहित प्रमुख वित्तीय संस्थानों के साथ साझेदारी की है.

माई ईवी स्टोर ने लॉन्च किया IME रैपिड इलेक्ट्रिक स्कूटर, सिंगल चार्ज पर दौड़ेगी 300 किलोमीटर

इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी माई ईवी स्टोर ने भारतीय बाजार में अपने नए इलेक्ट्रिक स्कूटर IME Rapid को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में प्रति चार्ज 300 किलोमीटर तक की रेंज मिलने का दावा किया है और इसकी 80 किमी प्रति घंटे है. वेरिएंट के आधार पर आईएमई रैपिड की कीमत 99,000 रुपये से 1.48 लाख रुपये के बीच रखी गई है.

इस तकनीक से मिलती है अधिक रेंज

MY EV स्टोर ने दावा किया है IME रैपिड की अधिक रेंज ब्रांड की स्मार्ट रेंज टेक्नोलॉजी (SRT) के कारण संभव है. यह सिस्टम सटीक रेंज का पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए बैटरी की स्थिति, मौसम की स्थिति, यातायात डेंसिटी और ड्राइविंग पैटर्न जैसे कारकों को शामिल करते हुए रियल टाइम डेटा का इंटेलिजेंट एनालिसिस करती है.

जल्द होगी अधिक शहरों तक पहुंच

IME रैपिड सबसे पहले बेंगलुरु में पेश किया जाएगा और उसके बाद पूरे कर्नाटक में इसकी बिक्री की जाएगी. कंपनी फिलहाल इसे बेंगलुरु में लॉन्च करने के लिए फ्रेंचाइज़ ओन्ड

कंपनी ऑपरेटेड (FOCO) मॉडल पर ध्यान केंद्रित कर रही है. कंपनी जल्द ही कर्नाटक के 15 से 20 शहरों में अपने आउटलेट्स का विस्तार करेगी.

तीन वेरिएंट्स में है उपलब्ध

IME रैपिड को शुरुआत में 3 अलग-अलग वेरिएंट में पेश किया गया है, जिसे एक बार चार्ज करने पर 100, 200 और 300 किलोमीटर की रेंज मिलेगी. 2000 W मोटर (2kWh मोटर) और क्रमशः 60V - 26/52/72 AH की बैटरी पैक से लैस यह स्कूटर 80 किमी प्रति घंटे की टॉप स्पीड से चल सकता है. MY EV स्टोर सभी ग्राहकों के लिए वाहनों की हेजल फ्री सर्विसिंग की सुविधा के लिए पूरे बेंगलुरु में वारंटी और स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता की पेशकश करेगी. MY EV स्टोर ने ग्राहकों के लिए आकर्षक, आसान और सिंपल फाइनेंस स्कीम के लिए कोटक महिंद्रा, श्रीराम फाइनेंस और मणप्पुरम फाइनेंस सहित प्रमुख वित्तीय संस्थानों के साथ साझेदारी की है. इसका मुकाबला सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर से होगा, जिसमें 212 km/चार्ज की रेंज मिलती है.

क्लाइमेट ट्रेंड्स ने जारी किया EV डैशबोर्ड, विशेषज्ञ बोले-नीतियों को और सुविधाजनक बनाने की जरूरत

देश के वाहन बाजार में इलेक्ट्रिक गाड़ियों (ईवी) की पैठ लगातार बढ़ रही है। ऐसे में क्लाइमेट थिंकटैंक व लाइमेट ट्रेंड्स ने 'व लाइमेट डॉट' के साथ मिलकर आज 'ईवी डैशबोर्ड' जारी किया। विशेषज्ञों ने कहा कि भारत में राष्ट्रीय और राज यों के स्तर पर बनी ईवी नीतियों को उपभोक्ताओं के प्रति और मित्रवत बनाने तथा इस सिलसिले में एक नियामक कार्ययोजना लागू करने की पूरी गुंजाइश है।

नई दिल्ली। देश के वाहन बाजार में इलेक्ट्रिक गाड़ियों (ईवी) की पैठ लगातार बढ़ रही है। ऐसे में क्लाइमेट थिंकटैंक क्लाइमेट ट्रेंड्स ने 'क्लाइमेट डॉट' के साथ मिलकर आज 'ईवी डैशबोर्ड' जारी किया। क्लाइमेट ट्रेंड्स की निदेशक आरती खोसला ने इसको जारी करते हुए कहा कि यह अनोखा डैशबोर्ड सरकार के वाहन पोर्टल की मदद से इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री से सम्बन्धित रियल टाइम डेटा लेकर उसे बेहद आसान और उपयोगकर्ता के लिये सुविधाजनक तरीके से पेश करता है, जिससे बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों की पैठ समेत विभिन्न स्तरों के बारे में त्वरित विश्लेषण और शोध किया जा सकता है।

नीतियों को उपभोक्ता के मित्रवत बनाने की जरूरत

विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में राष्ट्रीय और राज्यों के स्तर पर बनी ईवी नीतियों को उपभोक्ताओं के प्रति और मित्रवत बनाने तथा इस सिलसिले में एक नियामक कार्ययोजना लागू करने की पूरी गुंजाइश है। देश में लागू इलेक्ट्रिक वाहन नीतियों और उनकी प्रभावशीलता को समझने के लिये ईवी बिक्री विश्लेषण की आवश्यकता तथा अन्य पहलुओं पर विचार के लिए एक वेबिनार आयोजित किया गया।

क्लाइमेट डाट के निदेशक अखिलेश मागल ने ईवी डैशबोर्ड का जिक्र करते हुए कहा कि इस टूल के जरिये हमने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में मौजूद खामियों को ढूंढने पर ध्यान दिया है। इस डैशबोर्ड के जरिए उपयोगकर्ताओं को एक ऐसा मंच देने की कोशिश की गयी है जहां वे अपनी बात को बहुत प्रभावशाली तरीके से रख सकें। हालांकि, अभी यह डैशबोर्ड का पहला संस्करण ही है। भविष्य में इसे और बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी।

यह डैशबोर्ड सिर्फ शोधकर्ताओं और अध्ययनकर्ताओं के लिए ही नहीं, बल्कि उन पत्रकारों के लिए भी है जो इस पर कोई लेख लिखना चाहते हैं, इसलिए हमने यह सुनिश्चित किया है कि जो भी डाटा डैशबोर्ड पर डाले जाए वह बिल्कुल सटीक हों। हमारा यह भी उद्देश्य है कि पब्लिक नैरेटिव भी बना रहे क्योंकि किसी भी तरह का रूपांतरण करने में जनमत की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

क्लाइमेट डाट के अंकित भट्ट ने इलेक्ट्रिक व्हीकल डैशबोर्ड के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि इस डैश बोर्ड में सबसे पहले भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के बाजार के बारे में बताया गया है। इन वाहनों को चार श्रेणियां में बांटा गया है। इनमें मुख्यतः दो पहिया वाहन, तिपहिया वाहन, चार पहिया वाहन और बसें शामिल हैं। इसमें इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री का राज्यवार ब्यौरा भी दिया गया है।

देश का हर राज्य इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में आगे निकलने के लिये चुनौती पेश कर रहा है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को लेकर राज्यों की एक से बढ़कर एक नीतियों से उनकी यह मंशा जाहिर होती है। इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे नजर आता है, लेकिन इस राज्य में बिकने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों में एक बड़ा हिस्सा तिपहिया वाहनों का है।

इलेक्ट्रिक मोबिलिटी विशेषज्ञ नारायण कुमार ने ईवी नीतियों को और व्यापक तथा उपयोगकर्ताओं के हितों के प्रति और बेहतर बनाने की जरूरत पर जोर देते हुए वेबिनार में कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि राज्यों के स्तर पर भी मजबूत नियामक कार्य योजनाएं बनाने की जरूरत है। राज्यों को उनकी स्थिति के अनुरूप नीति बनाने की जरूरत है क्योंकि हर राज्य अपने आप में अलग है, इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम मजबूत नियामक कार्ययोजनाओं पर ध्यान दें ताकि चीजों को सतत तरीके से किया जा सके।

इलेक्ट्रिक वाहनों पर डिमांड साइड इंसेंटिव की पेशकश

उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री लगातार दोहरे अंकों में रिकॉर्ड की जा रही है और क्लाइमेट ट्रेंड्स एवं क्लाइमेट डॉट के डैश बोर्ड के मुताबिक भारत में सिर्फ छह राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान ही देश की कुल इलेक्ट्रिक वाहन बिक्री में 60% का योगदान कर रहे हैं। बाकी 40% हिस्सा देश के अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का है। कर्नाटक को छोड़कर बाकी सभी राज्यों ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर डिमांड साइड इंसेंटिव की पेशकश की है।

इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन की शोधकर्ता शिखा रुकाडिया ने नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर रोशनी डालते हुए कहा, ''यह सही है कि इलेक्ट्रिक वाहनों की पैठ देश के कुछ मुट्ठी भर राज्यों तक ही सीमित है। हम यह देख रहे हैं कि जो भी बढ़ोत्तरी हुई है उनमें से 80% हिस्सा दोपहिया वाहनों का है। सरकार ने समय-समय पर इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए नीतियां लागू की है लेकिन उनमें समय पर उतार-चढ़ाव भी देखा गया है। कई बार सब्सिडी की धनराशि घटाई गई है।

इलेक्ट्रिक मोबिलिटी विशेषज्ञ सौरभ कुमार ने सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिये चलायी जा रही योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा, ''आने वाले कुछ समय के दौरान हम यह देखेंगे कि पब्लिक ट्रांसिट सेक्टर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर बन जाएगा, जहां आप यह उम्मीद कर सकते हैं कि 2 लाख डीजल बसें इलेक्ट्रिक बसों में बदल जाएगी। इस साल अगस्त में भारत में उतनी ही इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीद-फरोख्त हुई जितनी कि पिछले साल बेची गई थीं।

सार्वजनिक परिवहन के माध्यमों से लगभग पांच करोड़ लोग रोजाना सफर करते हैं। सरकार इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए काफी काम कर रही है। अगर आप देखे तो वर्ष 2017 के पहले इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के बारे में बहुत कम लोग जानते थे लेकिन उसके बाद सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई अच्छी नीतियों के कारण इन वाहनों की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। यह सही है कि सरकार काफी कम कर रही है लेकिन निश्चित रूप से अभी इसमें और भी काम करना बाकी है। देश में जिस तरह का इकोसिस्टम बन रहा है उसके मद्देनजर इस क्षेत्र में अनंत संभावनाएं हैं।

भारत में अब इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का इकोसिस्टम बढ़ रहा है। वर्ष 2021 में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) पंजीकरण में 2020 की तुलना में 168% की भारी वृद्धि दर्ज की गई। भारत सरकार जीवाश्म ईंधन पर देश की निर्भरता को कम करने और ईवी को आंतरिक दहन इंजन (आइस) के प्राथमिक विकल्प के रूप में रखने के लिए विभिन्न कदम उठा रही है। मगर देश में ई-मोबिलिटी को बड़े पैमाने पर अपनाने के लिए अब भी बहुत कुछ करने की जरूरत है।

सीखने की उम्र

पीके खुराना

पंजाब के एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय के छात्रों को संबोधित करते हुए नामचीन बिजनेस गुरु शिव खेड़ा ने स्वीकार किया कि दो साल पहले तक उन्हें ईमेल करना नहीं आता था। सहायकों की टीम उनके काम निपटा देती थी। कोरोना काल में जब सारी दुनिया को लॉकडाउन से गुजरना पड़ा, दफ्तर बंद हो गए और अपने बहुत से काम खुद निपटाने की जरूरत आन पड़ी तो उन्होंने अपने पोते-पोतियों से ईमेल करना सीखा।

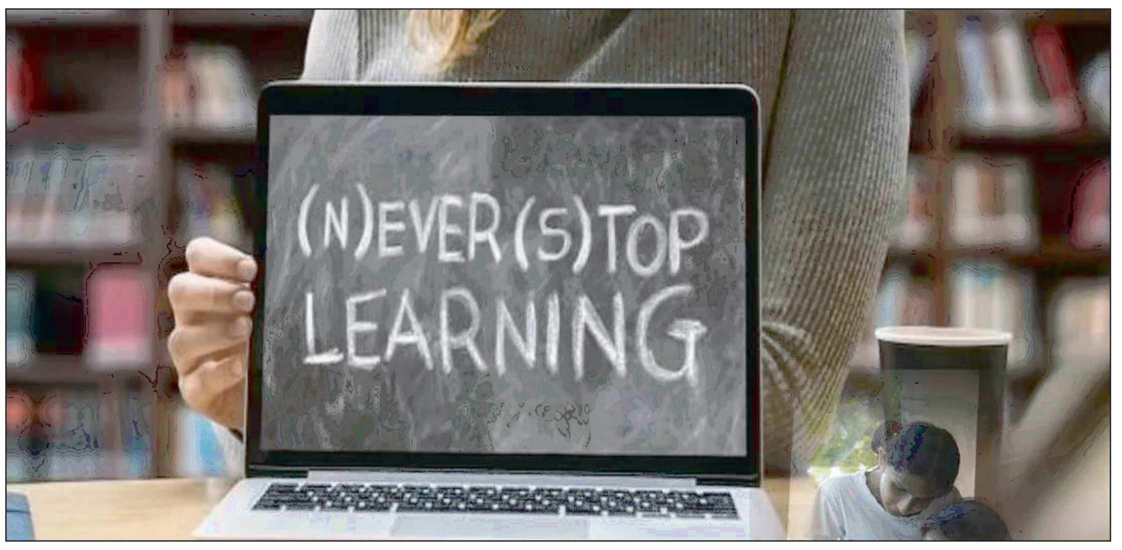

मेरा प्रयास सिर्फ इतना सा है कि हम जो नया ज्ञान अर्जित करें, उसे सिर्फ शौक ही न रहने दें बल्कि उसका आर्थिक लाभ भी लें। आज जब मैं हैपीनेस गुरु से आगे बढ़ कर स्पिरिचुअल हीलर यानी आध्यात्मिक चिकित्सक के रूप में प्रसिद्धि पा चुका हूं तो अपने पास आने वाले लोगों को ये बताने से गुरेज नहीं करता कि खुश रहने के लिए शौक पालिए, पर यदि आप उन्हें बिजनेस में भी बदल सकें तो सोने पर सुहागा होगा। मुझे खुशी है कि खुशनुमा गपशप सरीखी मेरी बातचीत के इस तरीके के कारण भी बहुत से नए बिजनेस खुले हैं, सफल हुए हैं, उनके कारण नए रोजगार बने हैं और हम सब देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती में विनम्र योगदान कर पा रहे हैं'

पंजाब के एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय के छात्रों को संबोधित करते हुए नामचीन बिजनेस गुरु शिव खेड़ा ने स्वीकार किया कि दो साल पहले तक उन्हें ईमेल करना नहीं आता था। सहायकों की टीम उनके काम निपटा देती थी। कोरोना काल में जब सारी दुनिया को लॉकडाउन से गुजरना पड़ा, दफ्तर बंद हो गए और अपने बहुत से काम खुद निपटाने की जरूरत आन पड़ी तो उन्होंने अपने पोते-पोतियों से ईमेल करना सीखा। कोरोना का सबसे बड़ा सबक यही है कि परिस्थितियां कब किसे विवश कर दें, कहना मुश्किल है, इसलिए जितना संभव हो, अपने कामों के लिए हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए। जहां तक संभव हो अपने कामों से संबंधित टूल्स का ज्ञान होना चाहिए, उन्हें प्रयोग करना आना चाहिए। सहायक उपलब्ध हों, और रूटीन के काम खुद न करने पड़ें तो बहुत अच्छा है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि आवश्यकता होने पर हम किसी का मुंह ताकने के लिए विवश न हो जाएं। हम सब जानते हैं कि कर्नल सैंडर्स ने 65 वर्ष की उम्र में केएफसी की स्थापना की जो आज दुनिया भर में फैला है। उस वक्त जब उन्होंने केएफसी की स्थापना की तो बिजनेस नया था। नए बिजनेस को संभालना, चलाना, कर्मचारियों का चयन, नियुक्ति, प्रशिक्षण और उन्हें टिकाए रखना, ग्राहकों को अच्छी क्वालिटी का स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध करवाना, कच्चे माल की खरीद, व्यवसाय का प्रचार आदि सब उन्होंने उसी उम्र में किया।

तब क्या चुनौतियां नहीं आई होंगी। पैंसठ साल की उम्र में कर्नल सैंडर्स ने उन चुनौतियों का मुकाबला करने के कुछ नए तरीके तो अवश्य सीखे ही होंगे। खुद मैं अपनी बात करूं तो बुढ़ापे की इस उम्र में भी मैं अब भी हर रोज कुछ न कुछ नया सीख रहा हूं। कोरोना के कारण मार्च 2020 में जब हमारे कार्यालय बंद हुए तो लगभग साल भर तक नहीं खुले। हम सब अपने-अपने घरों से ही काम कर रहे थे। सहायक नहीं थे। कार्यालय में बैठ कर बहुत से काम जो मैं टीम के विभिन्न सदस्यों को सौंप सकता था, तब संभव नहीं थे, इसलिए बहुत से काम खुद करने की जरूरत आन पड़ी तो उन्हें करना शुरू किया। जैसे कोई नन्हा बच्चा चलना सीखते हुए लडखड़ाता है, कई बार गिरता भी है, लेकिन फिर चलना शुरू कर देता है, वही मेरे साथ भी हुआ। सहायकों द्वारा किए जाने वाले जो काम मैं खुद करता था, उनकी गुणवत्ता और पैकेजिंग बहुत अच्छी नहीं होती थी, पर शुरुआत हो गई। बहुत से काम ठीक ढंग से करने सीख लिए, हालांकि बहुत से काम अभी भी सीखने की स्टेज पर ही हूं। अपने काम खुद करने की प्रेरणा मुझे अपनी पोती की उम्र की एक छोटी सी बच्ची से मिली। तनावमुक्त जीवन जीने का प्रशिक्षण देने के कारण लोग मुझे हैपीनेस गुरु के रूप में जानते हैं। पिछले वर्ष मैं उस वक्त हैरान रह गया जब मेरी पुस्तकों के प्रकाशक डा. विनीत गेरा ने मेरा परिचय श्रीमती नित्या मेहता से करवाया। नित्या जी की तेरह साल की बिटिया स्निग्धा मेहता ने अपने उपन्यास का दूसरा भाग लिखा था और उसका प्रकाशन भी मेरे प्रकाशक द्वारा ही होना था, अतः डा. गेरा ने मुझसे अनुरोध किया कि मैं स्निग्धा के उपन्यास की भूमिका लिख दूं। मैं यह जानकर चमत्कृत था कि इस छोटी सी बच्ची ने इस कच्ची उम्र में न केवल उपन्यास लिखना सीखा, बल्कि एक प्रकाशित लेखिका बनने का गौरव भी प्राप्त किया। कोरोना ने बहुत सी नौकरियां छीन लीं, बहुत से व्यवसाय बंद हो गए, कई घर उजड़ गए और बहुत से लोग भगवान को प्यारे हो गए। इस कठिन समय में बहुत से लोग निराश हुए, हताश हुए या डिप्रेशन में चले गए। इस कठिन समय में मुझे यही उचित लगा कि मैं अपने देशवासियों की हरसंभव सहायता करूं।

तब मैंने स्पिरिचुअल हीलर की अपनी सेवाओं को ऑनलाइन भी देना आरंभ किया और लोगों को रोगमुक्त होने में सहायता की। पत्रकारिता की मेरी पृष्ठभूमि के कारण मैं अपने पास आने वाले लोगों से कई तरह के सवाल पूछता था ताकि उनके बारे में अधिक से अधिक जानकर उनकी व्यक्तिगत उन्नति में भी सहायक हो सकूं। इसी दौरान मेरी मुलाकात आकाशवाणी शिमला, जालंधर, जयपुर, दिल्ली आदि केंद्रों के मुखिया रह चुके प्रसिद्ध साहित्यकार स्वर्गीय विश्व प्रकाश दीक्षित 'बटुक' की अड़सठ वर्षीय सुपुत्री सुश्री माधवी दीक्षित से हुई। वे भी आकाशवाणी में वरिष्ठ पदों पर रह चुकी हैं और रिटायरमेंट के बाद खाली बैठने के बजाय कुछ नया करने और सीखने का शौक उन्हें मेरे संपर्क में ले आया। बातचीत के दौरान सुश्री दीक्षित के एक कथन ने मेरे ज्ञान चक्षु खोले। उन्होंने कहा कि ज्यादातर भारतीय 'कर्स ऑफ नालेज', यानी ज्ञान के अभिशाप नामक रोग से ग्रसित हैं। 'कर्स ऑफ नालेज' का खुलासा करते हुए उन्होंने मुझे बताया कि आम भारतीय या तो यह मानता है कि वह सब कुछ जानता है और उसे कुछ भी नया सीखने की जरूरत नहीं है। इसका दूसरा पहलू यह है कि हमारे पास जो ज्ञान है, हम उसकी महत्ता नहीं समझते और उसे व्यवसाय बनाने या उससे आर्थिक लाभ लेने की कोशिश नहीं करते, तीसरा पहलू यह है कि हम बिना कोशिश किए ही यह मान लेते हैं कि अमुक काम हमारे बस का नहीं है और चौथा पहलू यह है कि अक्सर हम उम्र का बहाना बना कर कुछ नया सीखने से इन्कार कर देते हैं कि लोग क्या सोचेंगे।

उनका यह खुलासा हमें नई दिशा देने में समर्थ है। कोशिश किए बिना ही हार मान लेना गलत है, और कुछ नया करने या नया सीखने की कोई एक उम्र नहीं होती, हर उम्र में नया ज्ञान सीखा जा सकता है, नया कुछ किया जा सकता है। इसमें मैं अपनी ओर से इतना ही जोडऩा चाहूंगा कि हमारे पास बहुत सा ऐसा ज्ञान होता है, जिसे व्यवसाय में बदलकर उससे आर्थिक लाभ लेना संभव है। इसके लिए सिर्फ कल्पनाशक्ति की आवश्यकता है। स्पिरिचुअल हीलिंग के अपने शौक को मैंने व्यवसाय में बदला। तकनीक का सहारा लेकर हीलिंग का ऑनलाइन सिस्टम तैयार किया। आज भी मेरा वह अनुभव कायम है कि हर उम्र के लोग जीवन का उत्साह बनाए रखने के लिए कुछ न कुछ नया सीखना ही चाहते हैं। नई बातें सीखने से हमारा दिमाग चुस्त रहता है और भूलने की बीमारी नहीं घेरती। मेरा प्रयास सिर्फ इतना सा है कि हम जो नया ज्ञान अर्जित करें, उसे सिर्फ शौक ही न रहने दें बल्कि उसका आर्थिक लाभ भी लें। आज जब मैं हैपीनेस गुरु से आगे बढ़ कर स्पिरिचुअल हीलर यानी आध्यात्मिक चिकित्सक के रूप में प्रसिद्धि पा चुका हूं तो अपने पास आने वाले लोगों को ये बताने से गुरेज नहीं करता कि खुश रहने के लिए शौक पालिए, पर यदि आप उन्हें बिजनेस में भी बदल सकें तो सोने पर सुहागा होगा। मुझे खुशी है कि खुशनुमा गपशप सरीखी मेरी बातचीत के इस तरीके के कारण भी बहुत से नए बिजनेस खुले हैं, सफल हुए हैं, उनके कारण नए रोजगार बने हैं और हम सब देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती में विनम्र योगदान कर पा रहे हैं।

संपादक की कलम से

भारत अर्थात इंडिया

हमारे देश का सांस्कृतिक और पौराणिक नाम 'भारत' है। संविधान में 'इंडिया' नाम का भी उल्लेख है। संविधान की प्रस्तावना में लिखा है- 'इंडिया, जो भारत है, राज्यों का संघ कहलाया जाएगा।' यही संवैधानिक व्यवस्था जारी रही है। भारत और इंडिया हमारे देश के पूरक नाम रहे हैं, जिन पर हमें गौरव महसूस करना चाहिए। भारत जी-20 देशों की अध्यक्षता कर रहा है और 9-10 सितंबर को शिखर सम्मेलन होगा, जिसमें कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री भाग लेंगे। 'राष्ट्रपति भवन' ने विदेशी मेहमानों के लिए 9 सितंबर को रात्रि-भोज का आयोजन किया है। उसके निमंत्रण-पत्र में लिखा गया है-'प्रेसीडेंट ऑफ भारत'।' अभी तक 'प्रेसीडेंट ऑफ इंडिया' का चलन रहा है। अलबत्ता हिंदी में 'भारत के राष्ट्रपति' लिखने की भी परंपरा रही है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री मोदी ऑसियान समिट में शिरकत करने इंडोनेशिया जा रहे हैं। इस संदर्भ में लिखा गया है-'प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत'।' ये नए प्रयोग गलत नहीं हैं, लेकिन अचानक ऐसा बदलाव सामने आया है, तो अटपटा और संदेहास्पद जरूर लग रहा है। ऐसे बदलाव की जरूरत क्या थी? क्या मोदी सरकार संविधान में महत्त्वपूर्ण संशोधन के मंसूबे रखती है? क्या संविधान की प्रस्तावना में भी परिवर्तन किया जा सकता है? इनके जवाब संसद के विशेष सत्र के दौरान मिल सकते हैं, लेकिन हमारी जड़ें, हमारा परिचय और हमारी सांस्कृतिक विरासत 'भारत' में निहित है। 'विष्णु पुराण', 'ब्रह्म पुराण' और कई अन्य धार्मिक ग्रंथों में 'भारतम्' शब्द का उल्लेख मिलता है। लेकिन हमारे देश को आर्यावर्त, हिंद, हिंदुस्तान, भारतखंड, हिमवर्ष, जम्बूद्वीप आदि नामकरणों से भी संबोधित किया जाता रहा है। किसी को कोई आपत्ति नहीं रही। 2016 में एक याचिका के संदर्भ में सर्वोच्च अदालत ने फैसला दिया था कि इंडिया और भारत दोनों ही नाम प्रचलित रहेंगे। नागरिक अपनी इच्छा और पसंद के मुताबिक नाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। 'भारत' के अलावा 'इंडिया' के साथ भी मिथकीय कथाएं जुड़ी हैं। महारानी इंदुमती अयोध्या के सम्राट अज की धर्मपत्नी और महाराजा दशरथ की माता थीं। जब राजा राम अयोध्या के सिंहासन पर बैठे, तो उनके कालखंड में दादी इंदुमती का नाम भी प्रचलित था, जिसे आज हम 'इंडिया' कहते हैं। 'भारत' नाम राजा राम के छोटे भाई भरत के नाम पर पड़ा। किंवदन्ति यह भी है कि राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र का नाम भी भरत था। ऋषि कण्व ने भरत को 'चक्रवर्ती सम्राट' बनने का आशीर्वाद दिया था, लिहाजा उनके आधार पर हम 'भारत' बने। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जी के 'चक्रवर्ती पुत्र' भरत विश्व-विजयी सम्राट थे, लिहाजा देश का नाम 'भारत' पड़ा। ऐसी कई मिथकीय कथाएं और मान्यताएं होंगी, जो 'भारत' के सांस्कृतिक अतीत का खुलासा करती रही हैं, लेकिन 1947 में देश की आजादी के बाद जब संविधान ने आकार और स्वीकृति प्राप्त की, तो अनुच्छेद एक में 'इंडिया अर्थात भारत' का उल्लेख किया गया। यदि देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने 'भारत' शब्द का प्रयोग किया है, तो किसी प्रोटोकॉल का हनन नहीं किया गया है। हमारे 'राष्ट्रगान' में 'भारत भाग्य विधाता' लिखा गया है, तो भारत सरकार की कई परियोजनाओं के साथ 'इंडिया' शब्द लिखा गया है। हमारे केंद्रीय बैंक, उच्च शैक्षिक संस्थानों, अस्पतालों, चुनाव आयोग आदि के साथ भी 'इंडिया' शब्द आज भी नत्थी है। किसी को हटाने का कोई निर्णय और आदेश नहीं है। फिर सियासी चीखा-चिल्ली क्यों? देश में 'सदी के महानायक' अमिताभ बच्चन और उनकी सांसद-पत्नी जया बच्चन ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी है-'भारत माता की जय।' हमारे महान एवं विश्व चैम्पियन बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने भी 'भारत' को ही मूल नाम और परिचय माना है। ढेरों प्रतिक्रियाएं आना स्वाभाविक है।

राय

दोषी है आंगन का पेड़

इन पेड़ों के पक्ष में बहुत कुछ है, लेकिन ऐसे फैसलों की जद में आम हिमाचली के जीवन की मुश्किलें समझी नहीं जातीं। आपदा से राहत ढूंढ रहा हिमाचल ऐसी सख्तियां परवान चढ़ा रहा है, जो सामान्य लोगों के लिए किसी आफत से कम नहीं। अहम फैसलों में कई स्टोन क्रशर बंद कर दिए गए हैं। पर्यावरणीय लिहाज से ऐसे फैसलों की गूंज से सकारात्मक शाबाशियां मिल जाएं, लेकिन क्या विज्ञान की दृष्टि से यह सामाजिक न्याय की एकमात्र छड़ी है। कुछ इसी तरह पर्यावरण संरक्षण का मनोवैज्ञानिक प्रभाव पैदा करने के लिए छह प्रजातियों के पेड़ कटान पर रोक लगा दी है। अब आपके घर का आम वन विभाग की टोकरी में होगा, तो त्रियांबल, तुनी, पदम व रीठा भी घर के मालिकाना हक से कहीं अधिक जंगलात की अनुमतियों की पैदाइश करेगा। पर्यावरण संबंधी और भी कई फैसले हिमाचल की जीवनशैली में नश्तर की तरह खड़े रहते हैं, लेकिन इनसान से पेड़ों का रिश्ता घटा क्यों, इसकी चर्चा नहीं होती। किसी ने आज तक यह विश£षण नहीं किया कि हिमाचल के नागरिकों को वन संरक्षण के बदले मिलता क्या है। आज से पचास साल पहले की वास्तुकला को देखें, तो हिमाचल उस स्तर तक लकड़ी का इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। हम मजबूरन ऐसी इमारतें बना रहे हैं जिनकी बनावट में कम से कम लकड़ी का प्रयोग और अधिकतम स्टील, प्लास्टिक या एलयूमीनियम को खपाया जा रहा है। कभी धज्जी निर्माण शैली से घर बनते थे, लेकिन आज चाहकर भी कोई इसे अपना नहीं सकता। क्या हिमाचल की भौगोलिक परिस्थिति में परंपरागत नींव के पत्थर आज की स्थिति में उपलब्ध हो सकते हैं।

पहले खड्डु या दरियाओं को छान कर भवन निर्माण की सामग्री उपलब्ध हो जाती थी, लेकिन आज घर का निर्माण एक ऐसी गणना है, जो हिमाचल के बूते पूरी नहीं होती। बेशक हम सत्तर फीसदी जमीन पर जंगल उगाते हैं, लेकिन घर की छांव के लिए बाजार में उपलब्ध आयातित इमारती लकड़ी या वैकल्पिक सामग्री का इस्तेमाल करना हमारी मजबूरी है। बस्तियों में जंगल घुस सकता है, लेकिन बस्ती को जंगल की तरफ देखने की मनाही है। हिमाचल में घर बनाना एक अपराध की तरह विभिन्न विभागों के चक्कर काट रहा है। ऐसा कोई विभाग नहीं, जो जनता की मांग पर ऐसी भूमि की शिनाख्त कर सके। शहरी विकास विभाग या इसकी किसी एजेंसी ने मांग के आधार पर कोई नया शहर नहीं बसाया। करीब एक दशक पूर्व हिमुडा ने आवासीय मांग पर घर का सपना दिखाया, लेकिन पचहत्तर हजार के करीब आए आवेदन आज भी भ्रमित हैं। राजस्व रिकार्ड में टुकड़ों में बंटी जमीन का सौदा हो जाए, तो निर्माण की पैमाइश में बिजली या पेयजल की आपूर्ति के लिए युद्धरत माहौल कोर्ट कचहरी में बूढ़ा कर देता है। क्या कभी अंदाजा लगाया कि अपना घरौंदा बनाने की ख्वाहिश ने कितने लोगों को कानूनों की जिरह में फंसा दिया है। इस पर तुर्रा यह कि अगर कोई पुश्तैनी टुकड़ा मिल भी जाए, तो 16 प्रजातियों के पेड़ इतनी निगरानी तो कर ही लेंगे कि किसी का घर एक जन्म में पूरा न हो। बेशक आपदा के वर्तमान दौर ने बहुत कुछ छीन लिया, लेकिन क्या हम हिमाचली जनता की मांग और आपूर्ति में वन विभाग को न्यायाधीश बना कर न्याय कर रहे हैं। निजी उपयोग के लिए प्रदेश में बची हुई जमीन की अलग-अलग किस्में तो हमने बना दीं, लेकिन कभी यह किस्म छांटी गई जो रहने के लिए अति उत्तम है। निजी जमीन की दशा से कहीं बेहतर हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, कांगड़ा, सिरमौर और चंबा के कई क्षेत्रों में जंगल के तहत आ गई जमीन है, तो क्या असुरक्षित निजी जमीन की अदला बदली जरूरी नहीं। कम से कम सरकार यह तो बताए कि भविष्य के लिए आम हिमाचली कहां और कैसा घर बनाए।

प्रो. सुरेश शर्मा

क्या प्रदेश आपदा से सीख लेगा?

प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस में तालमेल हो। कुछ वर्षों से हिमाचल भी विकास की अंधी दौड़ में शामिल हो चुका है। विकास होना चाहिए, लेकिन प्रकृति की कीमत पर नहीं

बरसात तो पहले भी होती थी, लेकिन वर्ष 2023 की बेदर्दी मानसून हिमाचलवासियों को कभी न भूलने वाले गहरे जख्म दे गई। मात्र दो महीने की विनाशलीला ने इस सुंदर प्रदेश को तबाह तथा छलनी-छलनी कर दिया। इस बार जलप्रपात तथा भूस्खलन के भयानक मंजर ने यह भी समझाया कि हिमाचल वालो, अभी भी सुधर जाओ, कोई तुम्हारे आंसू पोंछने नहीं आएगा। इस बार यह भी पता चला कि मात्र दो महीने में लगभग 395 लोगों का असमय और अकारण मौत के मुंह में चले जाना, 349 लोगों का घायल होना तथा 40 का लापता होना कोई बड़ी घटना नहीं है। इस विनाशलीला में चारों ओर लाशें, बिखरते और गिरते आशियाने, बहते पुल, हर तरफ चीख-ओ-पुकार, सिसकियां, बिलखते लोग, अपनों के बिछड़ जाने का गम, मदद के लिए उठते हाथ, ईश्वर के लिए प्रार्थनाएं- सब कुछ था, लेकिन मानकों के अनुसार यह कोई बड़ी राष्ट्रीय आपदा या त्रासदी नहीं थी। बीघों जमीन का बहना, बागीचों का जलमग्न हो जाना, लगभग 1200 सडक़ों का बाधित होना, पथ परिवहन के लगभग 5000 रूट बंद होना, बिजली के लगभग 5000 ट्रांसफार्मर खराब होना, दस हजार पेयजल योजनाएं ठप्प हो जाना, 2457 घरों का गिरना, बहना तथा टूटना, 10569 घरों का आंशिक नुकसान, 1000 से अधिक गाडियों का जलप्रपात में बह जाना तथा परिणामस्वरूप 8604 करोड़ 88 लाख रुपए की बरबादी का आकलन कोई राष्ट्रीय आपदा नहीं होती? मात्र दो महीने के अन्तराल में हिमाचल के लोग भूस्खलन, बाढ़, बादल फटना, बिजली गिरना, ऑरेंज अलर्ट, रैड अलर्ट की चेतावनियां भयंकर तथा डरावनी बर्बादी देख तथा सुन कर भयभीत रहे।

इतनी तबाही के बाबजूद राष्ट्रीय आपदा घोषित न होना भी बड़ा प्रश्नचिन्ह है। बिहार, केरल तथा उत्तराखंड की त्रासदी में पूरे देश के लोगों ने वहां के लोगों का दर्द समझ कर प्रधानमंत्री राहत कोष तथा मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए अंशदान दिया है। हैरानी की बात है कि इस सुंदर, आकर्षक तथा छोटे से राज्य हिमाचल प्रदेश में घटित इस भयंकर त्रासदी के लिए कहीं से भी मदद के हाथ नहीं उठ सके। हिमाचल प्रदेश की जानी मानी फिल्मी हस्तियों का इस विपत्ति में कोई भी सहयोग न मिलना भी कल्पना से परे है। केवल हरियाणा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा राजस्थान की सरकारों ने 56 करोड़ रुपए भेज कर संकट के समय हिमाचल प्रदेश के आंसू पोंछने की कोशिश की है। स्वतन्त्र पत्रकार रवीश कुमार का यह कहना कि चंद्रयान की सफलता के शोर में दिल्ली से अंतरिक्ष में चांद बहुत पास दिखा, लेकिन राजधानी के बहुत पास जलप्रलय से बर्बाद हिमाचल प्रदेश के लोगों की चीख-ओ-पुकार नहीं सुना जाना बहुत कुछ सोचने पर विवश करता है। केन्द्र सरकार ने इस आपदा में कुल मिलाकर लगभग साढ़े आठ सौ करोड़ जारी किए हैं जो कि 8604 करोड़ 88 लाख की भरपाई के लिए बहुत ही कम हैं। प्रदेश में इन हालात के मद्देनजर नजर केन्द्र सरकार से राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की दरकार थी, ताकि प्रदेश के पुनर्निर्माण तथा फिर से पटरी पर लाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती। इस समय पर्यटकों के न आने से हिमाचल का पर्यटन उद्योग ठप्प हो चुका है। वर्तमान हालात में सेब से लगभग 5500 करोड़ रुपए की आर्थिकी को संभालना प्रदेश सरकार के लिए चुनौती बन गया है। सब्जियों तथा फलों की ढुलाई तथा उन्हें मण्डियों तक पहुंचाना मुश्किल हो गया है। वित्तीय संकट के कारण प्रदेश सरकार कोई आर्थिक मदद देने की स्थिति में नहीं है। यह ठीक है कि राजनीति हमारे जीवन का एक अटूट अंग है, लेकिन इस संकट के समय में प्रदेश की सरकार, प्रदेशवासियों, नीति निर्माताओं, प्रशासकों तथा जनता को व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठ कर प्रदेश के सतत विकास के बारे में सोचना होगा। विभिन्न राजनीतिक दलों को अपनी आत्मा की आवाज को सुन कर प्रदेश के भविष्य के बारे में चिंतन तथा विश्लेषण करना चाहिए। भविष्य की चुनौतियों को मद्देनजर रखते हुए सरकार को निम्नलिखित कड़े फैसले लेने की आवश्यकता है:

1. आपदा के समय हिमाचल प्रदेश को किसी पर निर्भर न होना पड़े, इसलिए विशेष आपदा कोष स्थापित किया जाना चाहिए। इस समय लगभग 10 हजार करोड़ से अधिक के नुकसान की भरपाई के लिए प्रदेश सरकार के पास कम से कम तीन गुना जमा पूंजी अपेक्षित थी। 2. भवन निर्माण के लिए कड़े नियमों तथा उनकी अनुपालना अति आवश्यक है। होटल निर्माण, उद्योग निर्माण, बिजली-पानी परियोजनाओं तथा धर्मस्थल निर्माण की स्थापना के लिए विशेष निरीक्षण सहित अनुमति ली जानी चाहिए। 3. मन्दिरों, मस्जिदों, गुरद्वारों तथा गिरजाघरों के आस्था के सैलाब से बनने वाले बेतरतीब निर्माण कार्यों पर रोक लगनी चाहिए। धार्मिक स्थलों का निर्माण भी नियमपूर्वक होना चाहिए। 4. प्रदेश में आने वाले पर्यटकों के लिए स्पष्ट तथा कड़ी पर्यटक नीति बनाई जानी चाहिए। प्रदेश के चार मुख्य द्वारों पर उनका विधिवत पंजीकरण होना चाहिए। पर्यटकों से उपयोग तथा उपभोग पर्यावरण टैक्स लिया जाना चाहिए। 5. अन्धाधुंध जंगलों के कटान, सडक़ निर्माण, नदी-नालों के अतिक्रमण तथा खड्डों के भूमि कटान पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। भू-माफियाओं, खनन माफियाओं, माइनिंग, बजरी, रेत तथा स्टोन क्रशर मालिकों, बिल्डरों तथा ठेकेदारों पर सरकार की लगाम होनी चाहिए। प्रशासन, पुलिस तथा कानून व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त होनी चाहिए। इस संदर्भ में राजनीतिक दखल तथा भाई-भतीजावाद न होकर 'जीरो टॉलरेंस' होनी चाहिए। 6. पर्यटन के कारण मनाली, कुल्लू, मंडी, धर्मशाला, शिमला तथा सोलन आदि शहर वर्तमान में कंक्रीट के जंगल बन चुके हैं। इन शहरों में अब बेतरतीब निर्माण पर रोक लगनी चाहिए। भूकम्प, बाढ़, हिमपात, आगजनी तथा किसी भी आपदा की दृष्टि से यह बहुत ही आवश्यक है। 7. प्रदेश स्तर तथा प्रत्येक जिला में आपदा प्रबंधन तथा नियंत्रण के लिए एक विशेष सशक्त तथा सुदृढ़ विभाग की स्थापना की जानी चाहिए जिसमें आपदा प्रबंधन के लिए शिक्षित एवं प्रशिक्षित लोगों की व्यवस्था हो। प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस, होमगार्ड में तालमेल हो। कुछ वर्षों से हिमाचल प्रदेश भी भौतिकवाद तथा विकास की अंधी दौड़ में शामिल हो चुका है। विकास होना चाहिए, लेकिन मानवीय जीवन तथा प्रकृति की कीमत पर नहीं।

अंततः जमीन के टुकड़े पर

'आओ उसी आकाश के नीचे छुपा जाए, जमीं का कोई टुकड़ा नसीब में आए।' आपदा जिस कद्र गुजर गई उससे हिमाचल में इनसान का आधार कमजोर पड़ गया। घाव चेहरे के जब जमीं पर उतर आएं, प्रगति के दिन और रातें कांपती हैं। इसी एहसास में हिमाचल सरकार के पिछले दो महीनों की समीक्षा होनी चाहिए। ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जो पहले नहीं हुआ। ऐसा बहुत कुछ सुना जा रहा, जो पहले नहीं सुना। नींद में सुला दिए गईं रिपोर्टें, सर्वेक्षण व हिदायतें अब सवालिया निशान बन कर हाजिर हैं, तो यह वक्त नीतियों, कार्यक्रमों, प्राथमिकताओं, सामाजिक संस्कारों और सरकार के राजनीतिक श्रृंगारों को बदलने का है। अगर समाज को हक है कि सरकार से पूछे, तो उन मेहरबानियों पर उगी वक्त की काई को भी हटाना होगा। जाहिर है आपदा ने पूरे हिमाचल के सामने जो दर्पण खड़ा किया है, उसकी दरारों में झांकते हुए केवल सरकार को ही नहीं सीखना है, बल्कि समाज को भी यह देखना है कि प्रदेश में राज्य का नया आचरण व चरित्र खड़ा करें। अभी केंद्र सरकार द्वारा वाया सुप्रीम कोर्ट 13 हिमालयी राज्यों की 'कैरिंग कैपस्टी' की योजना बनाने के निर्देश देने की अरदास हुई है। इसे सही परिप्रेक्ष्य में देखा, सुना और किया जाए, तो विकास के बीच उगते नासूर को खत्म किया जा सकता है, लेकिन फर्ज की हिदायतें तो केंद्र से नीतियों की राह बटोरना चाहती हैं। हिमालयी राज्य केवल पर्यावरण का भंडार नहीं, मानव अस्तित्व का भौगोलिक व जलवायु परिस्थितियों से मुकाबला भी है।

इसलिए यह स्वतंत्र रूप से अपनी देखभाल या अनिवार्य मानदंडों का पालन नहीं कर सकते और न ही राष्ट्रीय योजनाओं में आबादी के आधार पर न्याय प्राप्त कर सकते हैं। अब वक्त आ गया है जब हिमालयी तथा समुद्र तटीय राज्यों के लिए राष्ट्रीय योजनाएं, अनुसंधान, तकनीक, नवाचार तथा विकास का ढांचा अलग से सुनिश्चित किया जाए। हम पिछले पंद्रह सालों से सुझाव दे रहे हैं कि हिमालयी राज्यों को सुरक्षित, आत्मनिर्भर तथा न्याय की दृष्टि से संबल देना है, तो पर्वतीय राज्य विकास मंत्रालय की स्थापना करनी होगी। देश की वर्तमान राजनीति जिन पैमानों से बनती व बंटती है, वहां पर्वतीय राज्य आबादी के आधार पर हाशिए से बाहर हो जाते हैं। भारतीय सुरक्षा बलों में पर्वतीय जज्बा जब तक खुले मन से भर्ती होने की असीमित संभावना में परिलक्षित होता था, रोजगार का यह पहलू परवान चढ़ता था, लेकिन अब आबादी का कोटा हिमालयी राज्यों को किनारे लगा देता है। कभी वित्त आयोग की सारी सिफारिशें हिमालयी राज्यों के पक्ष में केंद्र से लागत का नब्बे प्रतिशत दिला देती थी, लेकिन जब धर्मशाला-शिमला जैसे शहर, स्मार्टसिटी परियोजना में आए तो लागत 50 : 50 प्रतिशत के आधार पर हो गई। इसी तरह अब केंद्र की मदद से इलेक्ट्रिक वाहनों की खेप बड़े शहरों की रखवाली कर रही है, तो हिमाचल के मनाली, शिमला, मकलोडगंज व कसौली की 'कैरिंग कैपस्टी' के आकलन की जरूरत में बसों का यह तोहफा क्यों आबादी-आबादी खेल रहा है। केंद्र की हर योजना आबादी-आबादी खेलकर हिमालयी राज्यों को मजबूर करती है कि ये अपने आर्थिक संसाधनों को तराशते-तलाशते आपदा के खतरे मोल ले लें। ऐसे में एनएच के मजमून को हिमालयी राज्यों के संदर्भ में केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी अगर सुरंग रास्तों के विकल्प से जोडऩे की इच्छा प्रकट कर रहे हैं, तो यह भविष्य को संवारने का संकल्प हो सकता है। दूसरी ओर हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपदा प्रभावितों के लिए छह-छह मरला जमीन उपलब्ध कराने के लिए योजना शुरू कर दी है। यह सही समय पर लिया गया राहत भरा कदम है, लेकिन पहाड़ के ये मरले अति सुरक्षित होंगे या जिंदगी भर की सुरक्षा के लिए कहां ढूंढी जाए दो गज जमीन। पहाड़ को हम खुद बदनाम कर रहे हैं, हमने पर्यावरण सुरक्षा के मुहावरों में पहले ही जीने की आबरू लुटा दी या बेहतर जमीन को वन बना दिया। क्या हमीरपुर, ऊना, कांगड़ा, बिलासपुर व मंडी जैसे जिलों की लगभग समतल जमीन को जंगल से वापस लेकर हम भविष्य का सुरक्षित रेखांकन करने के लिए कभी प्रयास करेंगे या हिमालयी राज्यों के प्रयोग, उपयोग या प्रकोप में खुद को मनहूस मान लेंगे।

G20 सम्मिट: ये हैं दुनिया के 10 सबसे अमीर देश, वर्ल्ड इकोनॉमी को संभालने में देते हैं बड़ा योगदान

Richest Nations in G20 जी-20 सम्मेलन 9 और 10 सितंबर को राजधानी दिल्ली में होगा। यह पहली बार है कि किसी दक्षिण एशियाई देश ने विश्व नेताओं के इतने प्रभावशाली समूह की मेजबानी करेगा। ऐसे में आज हम आपको बताते हैं कि दुनिया के 10 सबसे अमीर देशों के बारे में जो जी-20 में हिस्सा ले रहे हैं। पढ़िए क्या है पूरी खबर।

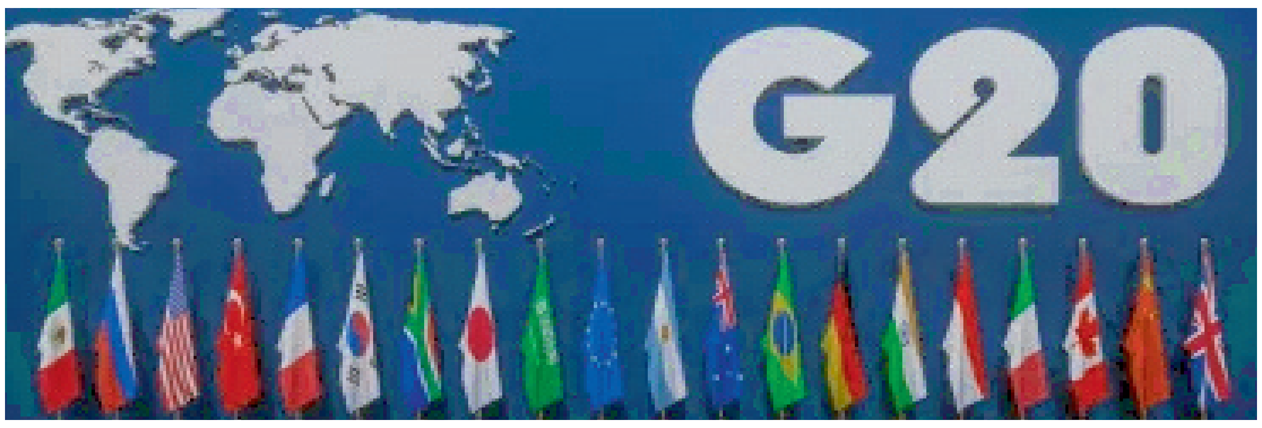

नई दिल्ली। आगमी 9 और 10 सितंबर को राजधानी दिल्ली में G-20 सम्मेलन होने वाला है। यह पहली बार है जब कोई दक्षिण एशियाई देश विश्व नेताओं के इतने शक्तिशाली समूह की मेजबानी कर रहा है।

आपको बता दें कि दुनिया के सबसे अमीर और सबसे शक्तिशाली देशों के नेता दो दिवसीय जी-20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने दिल्ली आ रहे हैं।

इन देशों के पास 85 प्रतिशत जीडीपी

जी-20 देशों की अगर आप अर्थव्यवस्था को मिला दें तो यह दुनिया की जीडीपी का 85 प्रतिशत होता है। ऐसे में यह जानना बेहद दिलचस्प होगा की दुनिया के वो ऐसे कौन से 10 अमीर देश हैं जो इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं।

इन 10 देशों की सूची इन देशों के जीडीपी के आधार पर तैयार की गई है। इन देशों की जीडीपी का सोर्स वर्ल्ड बैंक के 2021 का डेटा है। इसी के अनुसार यह लिस्ट तैयार की गई है।

यूएसए

दुनिया का सबसे शक्तिशाली और अमीर देश यूनिइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका (यूएसए) है। इस देश की जीडीपी 23 ट्रिलियन यूएस डॉलर से भी अधिक है। इसी वजह से यूएसए 10 अमीर देशों की लिस्ट में पहले स्थान पर है।

चीन

चीन इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर है। चीन की जीडीपी 17.73 ट्रिलियन यूएस डॉलर है।

जापान

इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर जापान है। जापान की जीडीपी 4.94 ट्रिलियन यूएस डॉलर है।

जर्मनी

इस लिस्ट में चौथे स्थान पर जर्मनी है। जर्मनी की जीडीपी 4.26 ट्रिलियन यूएस डॉलर है।

भारत

इस लिस्ट में पांचवें स्थान पर भारत है। भारत की जीडीपी 3.18 ट्रिलियन यूएस डॉलर है। हालांकि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि भारत की जीडीपी 3.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर के स्तर के पार कर चुकी है।

यूनाइटेड कंगडम (यूके)

इस लिस्ट में छठे स्थान पर यूके है। यूके की जीडीपी 3.13 ट्रिलियन यूएस डॉलर है।

फ्रांस

इस लिस्ट में सातवें स्थान पर फ्रांस है। फ्रांस की जीडीपी 2.96 ट्रिलियन यूएस डॉलर है।

इटली

इस लिस्ट में आठवें स्थान पर इटली है। इटली की जीडीपी 2.11 ट्रिलियन यूएस डॉलर है।

कनाडा

इस लिस्ट में नौवें स्थान पर कनाडा है। कनाडा की जीडीपी 1.99 ट्रिलियन यूएस डॉलर है।

ब्राजील

इस लिस्ट में दसवें स्थान पर ब्राजील है। ब्राजील की जीडीपी 1.61 ट्रिलियन यूएस डॉलर है ॥

निवेशकों के लिए कमाई का एक और मौका, अगले हफ्ते बाजार में IPO ला रही है ये कंपनी

आईपीओ में निवेश करने वालों के लिए एक बार फिर से निवेश का नया अवसर आने वाला है। वायर और केबल निर्माता आरआर काबेल लिमिटेड अगले सप्ताह आईपीओ लॉन्च करेगी। कंपनी के शेयर बीएसई और एनएसई पर सूचीबद्ध हैं। आईपीओ से पहले कंपनी ने अपने फ्रेश इश्यू साइज को घटा दिया है। पहले कंपनी ने 225 करोड़ रुपये के फ्रेश इश्यू जिसे घटाकर 180 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

नई दिल्ली, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओ) में निवेश करने वाले के लिए एक बार फिर से चांदी होने वाली है। तार और केबल निर्माता आरआर काबेल लिमिटेड (RR Kabel Ltd) बाजार में अगले हफ्ते अपना आईपीओ लाने जा रही है। कंपनी के इक्विटी शेयर बीएसई और एनएसई पर सूचीबद्ध होंगे।

कब खुल रहा है आईपीओ?

आरआर काबेल लिमिटेड 13 सितंबर को आईपीओ ऑफर खोलेगी। कंपनी ने आईपीओ में अपने फ्रेश इश्यू का आकार घटाकर 180 करोड़ रुपये तक करने का फैसला किया है।

आपको बता दें कि यह आईपीओ 15 सिंतबर को कारोबारी समय के बाद बंद होगा। कंपनी इस आईपीओ में ओएफएस की भी पेशकश करेगी।

कंपनी ने घटाया फ्रेश इश्यू का साइज

रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (आरएचपी) के अनुसार, कंपनी ने इक्विटी शेयरों के फ्रेश इश्यू का आकार 225 करोड़ रुपये के पहले लक्ष्य से घटाकर 180 करोड़ रुपये कर दिया है। ओएफएस में प्रवर्तकों और अन्य शेयरधारकों द्वारा 1.72 करोड़ से अधिक इक्विटी शेयर बेचे जाएंगे।

ओएफएस में शेयर बेचने वालों में महेंद्रकुमार रामेश्वरलाल काबरा, हेमंत महेंद्रकुमार काबरा, सुमीत महेंद्रकुमार काबरा, काबेल बिल्डकॉन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड और राम रत्ना वायर्स लिमिटेड शामिल हैं।

निजी इक्विटी फर्म टीपीजी कैपिटल, जिसके पास आरआर काबेल में 21 प्रतिशत हिस्सेदारी है, ओएफएस के तहत कंपनी में अपनी हिस्सेदारी आंशिक रूप से बेचेगी।

कंपनी कहां करेगी इन पैसों का उपयोग?

कंपनी ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लिए गए कर्ज को पूर्ण या आंशिक रूप से कम करने के लिए फ्रेश इश्यू से प्राप्त शुद्ध आय के 136 करोड़ रुपये का उपयोग करने का प्रस्ताव रखा है।

आपको बता दें कि एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एचएसबीसी सिक्योरिटीज एंड कैपिटल मार्केट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड और जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड इस इश्यू के बुक-रनिंग लीड मैनेजर हैं।

आरआर ग्लोबल ग्रुप का हिस्सा आरआर काबेल ने 2021-22 में 214 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट और 4,386 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया था।

सुनील मित्तल ने अफ्रीका में दो बार जलाए हाथ, नहीं मानी हार, एयरटेल को ऐसे बनाया ग्लोबल ब्रांड

एयरटेल ने अफ्रीका में सफलता हासिल कर ली है। आज अफ्रीका में एयरटेल एक जानी-मानी कंपनी है। कंपनी के चेयरमैन सुनील मित्तल को अफ्रीका में कई बार असफलता का सामना करना पड़ा था। एयरटेल ने Zain Telecom के अफ्रीकी देशों का अधिग्रहण किया और सब्सक्राइबर बेस को बढ़ाया। कंपनी ने अफ्रीका में लो टैरिफ स्ट्रैटेजी अपनाई।

नई दिल्ली। भारती एयरटेल (Bharti Airtel) ने लगातार खुद को कंप्टीशन में बनाए रखा है। मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) की कंपनी रिलायंस जियो (Reliance Jio) ने जब साल 2016 में टेलिकॉम सेक्टर में धमाकेदार एंट्री की थी। इस दौरान कई कंपनियों का बोरिया बिस्तर बंद हो गया था। कई कंपनियां अब भी इस झटके से नहीं उबर पाई हैं। लेकिन एयरटेल लगातार दौड़ में बना हुआ है। कंपनी के चेयरमैन सुनील मित्तल (Sunil Mittal) चुनौतियों से हार नहीं मानते हैं। अफ्रीका में भी एयरटेल को दो बार असफलता हाथ लगी थी। लेकिन सुनील मित्तल ने हार नहीं मानी और अफ्रीका में एयरटेल को सफलता दिखाई। अफ्रीका में किसी भी टेलीकॉम कंपनी के लिए सफलता पाना आसान नहीं है। आखिर सुनील मित्तल ने कैसे एयरटेल को कांप्टीशन में बनाए रखा है। किस तरह से उन्होंने एयरटेल को अफ्रीका में बड़ा ब्रांड बनाया। आइए आपको बताते हैं एयरटेल की सफलता के बारे में।

अफ्रीका में लगातार किए प्रयास

भारती एयरटेल (Bharti Airtel) भी भारत के बाहर अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुकी है। एयरटेल ने साल 2010 में अफ्रीका में एंट्री की थी। सुनील भारती मित्तल इससे पहले भी दो बार अफ्रीका में कारोबार शुरू करने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन सफल नहीं हुए थे। तीसरी बार में उनके हाथ सफलता लगी। एयरटेल ग्रुप ने Zain Telecom के 15 अफ्रीकी देशों में BV परिचालनों का अधिग्रहण किया था। यह सौदा 10.7 अरब डॉलर का रहा था। सौदे के लिए एयरटेल ग्रुप ने 8.5 अरब डॉलर का कर्ज लिया था। इसके बाद जो एंटिटी अस्तित्व में आई, उसका नाम है एयरटेल अफ्रीका।

ऑल टाइम लो पर बंद हुआ रुपया, लगातार चौथे दिन टूटकर 83.23 पर बंद हुई भारतीय करेंसी

परिवहन विशेष न्यूज

अमेरिकी मुद्रा में मजबूती और विदेशी पूंजी के आउटफ्लो के कारण रुपये में आज लगातार चौथे दिन गिरावट आई। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया आज 10 पिप गिरकर 83 .23 रुपये के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ। इंटरबैंक करेंसी एक्सचेंज पर रुपया आज 83 .15 पर खुला और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 83 .12-83 .23 के दायरे में कारोबार किया। पढ़िए क्या है पूरी खबर।

नई दिल्ली। मजबूत अमेरिकी करेंसी और विदेशी पूंजी के आउटफ्लो के बीच आज रुपये में लगातार चौथे दिन गिरावट दर्ज की गई। आज अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 10 पैसे गिरकर 83.23 के अपने जीवनकाल के निचले स्तर पर बंद हुआ।

इस वजह से भी गिरा रुपया

विदेशी मुद्रा व्यापारियों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की ऊंची कीमतों ने भी निवेशकों की भावनाओं पर असर डाला है। व्यापारियों के मुताबिक भारतीय शेयर बाजार में जारी तेजी के कारण रुपये और अधिक गिरने से बच गया।

समाचार एजेंसी पीटीआई से मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के फॉरेक्स और बुलियन विश्लेषक गौरांग सोमैया ने कहा कि

चीन के निराशाजनक व्यापार संतुलन आंकड़ों के बाद रुपये पर दबाव और कमजोरी बनी हुई है। रुपये में कमजोरी चीनी युआन में कमजोरी के कारण भी आई, जो पिछले एक साल में सबसे निचले स्तर पर आ गई।

कच्चा तेल 90 डॉलर के स्तर को पार

तेल उत्पादक देशों द्वारा इस साल दिसंबर तक आपूर्ति कटौती को बढ़ाने पर सहमति के बाद कच्चे तेल की कीमत 90 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल के स्तर को पार कर गई। जबकि सुरक्षित मांग के कारण डॉलर स्थिर रहा।

आज कितने पर खुला था रुपया?

इंटरबैंक फॉरेन एक्सचेंज में आज

रुपया 83.15 पर खुला और डॉलर के मुकाबले 83.12 से 83.23 के दायरे में कारोबार किया। आज रुपया डॉलर के मुकाबले 83.23 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ, जो पिछले बंद से 9 पैसे की गिरावट दर्शाता है।

अब तक 60 पैसे गिर चुका है रुपया

सोमवार से रुपये में 60 पैसे की गिरावट आई है, जब यह डॉलर के मुकाबले 9 पैसे गिरकर 82.71 पर बंद हुआ था। मंगलवार को रुपये में 33 पैसे की गिरावट आई, जो इस सप्ताह की सबसे तेज गिरावट है।

डॉलर इंडेक्स हुआ मजबूत

आपको बता दें कि विश्व की 6 करेंसी के मुकाबले डॉलर की ताकत का अंदाजा लगाने वाला डॉलर इंडेक्स 0.09 प्रतिशत बढ़कर 104.95 पर पहुंच गया। वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड वायदा 0.39 प्रतिशत गिरकर 90.25 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था।

एक्सचेंज डेटा के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) गुरुवार को पूंजी बाजार में शुद्ध विक्रेता थे, क्योंकि उन्होंने 758.55 करोड़ रुपये के शेयर बेचे।

खराब नेटवर्क के कारण नहीं कर पा रहे हैं UPI, इस तरह आसानी से करें ऑफलाइन यूपीआई पेमेंट

देश में कैशलेस लेनदेन में UPI की सबसे बड़ी भूमिका है। लेकिन यह असुविधा एक बड़ी समस्या तब बन जाती है यदि आपके पास नकदी नहीं है और आपने कोई सामान खरीदा है लेकिन खराब नेटवर्क के कारण भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अब घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि ऑफलाइन यूपीआई पेमेंट कैसे करें।

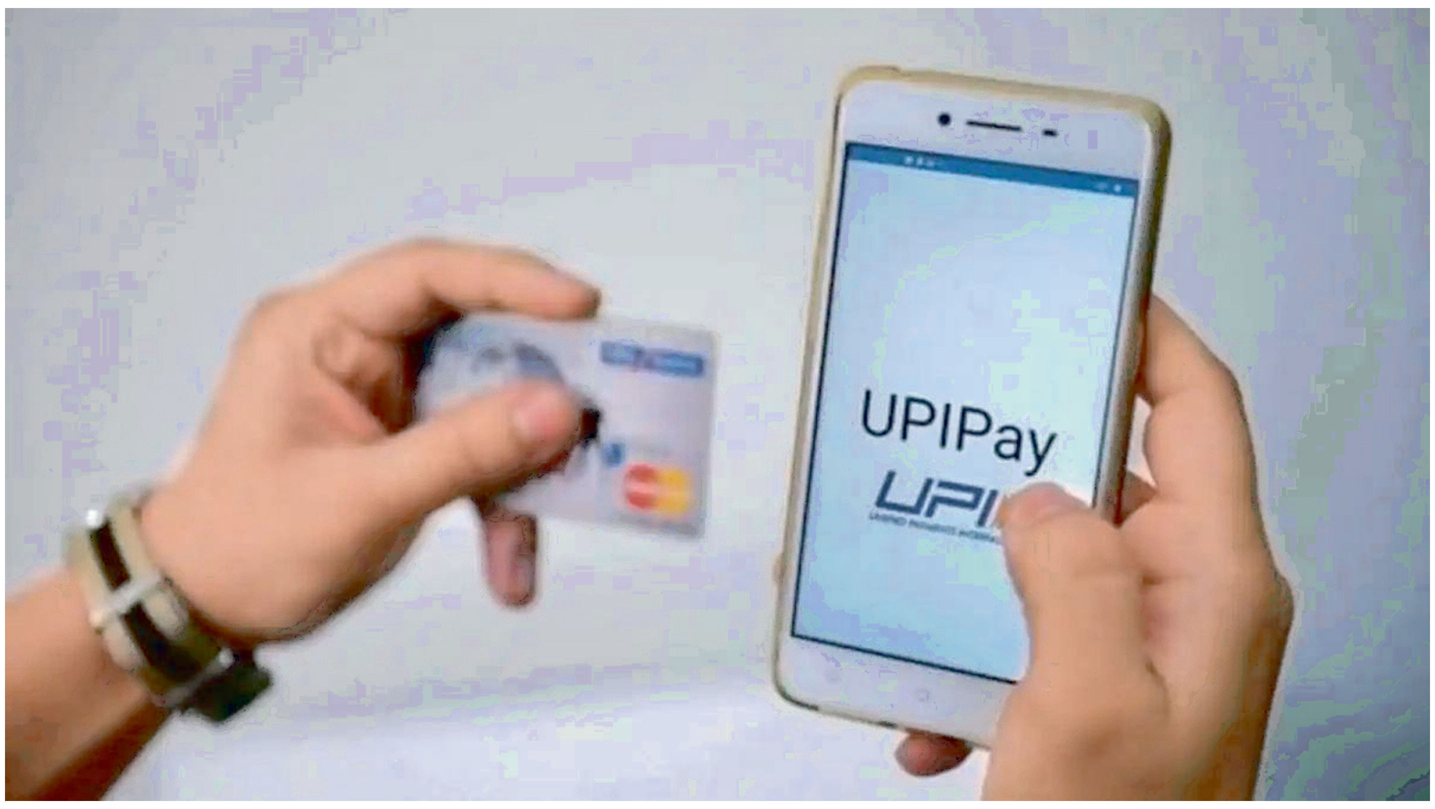

नई दिल्ली, देश में कैशलेस ट्रांजैक्शन हर बीतते साल बढ़ता जा रहा है। कैशलेस ट्रांजैक्शन में सबसे बड़ा हाथ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) का है। इसका आसान इंटरफेस और सुरक्षित एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा भेजने की सुविधा से लोगों को यह काफी पसंद भी आ रहा है।

आजकल आप देश में लगभग हर जगह यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। चाहे किराना दुकान हो, रेस्तरां हो, पेट्रोल पंप हो, रिक्शा वाला यहां तक की आप सब्जी वाले को भी आसानी से यूपीआई कर सकते हैं। हालांकि कभी-कभी लोगों को खराब नेटवर्क के कारण यूपीआई पेमेंट करने में असुविधा हो सकती है।

यह असुविधा तब बड़ी परेशानी का रूप ले सकती है जब आपके पास कैश न हो और आपने कुछ सामान खरीदा लेकिन खराब नेटवर्क के कारण आप पेमेंट नहीं कर पाएं। लेकिन अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप ऑफलाइन यूपीआई पेमेंट कैसे कर सकते हैं।

कैसे करें ऑफलाइन यूपीआई पेमेंट?

ऑफलाइन यूपीआई पेमेंट के लिए आपको एक कोड का इस्तेमाल करना होगा। आपको अपने फोन से *99# कोड को डायल करना होगा।

इसके बाद आपकी स्क्रीन पर एक फ्लैश मैसेज आएगा जिसमें सात विकल्प दिखाई देंगे।

इन विकल्पों में पैसे भेजना, पैसे का अनुरोध करना, अपनी शेष राशि की जांच करना और अपने लंबित अनुरोधों को देखना शामिल है।

इसके बाद आप वो ऑप्शन चुने जो आपको चाहिए। इसके लिए आपको उस विकल्प के आगे लिखा नंबर टाइप कर भेजना होगा।

पहला विकल्प है पैसे भेजना, तो ऐसे में 1 टाइप करें और भेज दें। इसके बाद आपको पांच विकल्प दिखाई देंगे।

आपको अपने फोन में पहले से सेव मोबाइल नंबर, यूपीआई या किसी लाभार्थी को पैसे भेजने का विकल्प मिलेगा।

आप यूपीआई से पैसे भेजना चाहते हैं इसलिए यूपीआई का ऑप्शन चुनें।

आपसे यूपीआई आईडी दर्ज करने के लिए कहा जाएगा, जहां आप पैसे भेजना चाहते हैं।

आप यूपीआई आईडी दर्ज करें और फिर वह राशि दर्ज करें जिसे आप भेजना चाहते हैं।

रकम भेजने से पहले आपको रकम भेजने का कारण बताना होगा।

इसके बाद आपको अपना यूपीआई पिन डालना होगा, जैसे आप अपने यूपीआई ऐप में करते हैं। ये करते ही आपका पैसा सफलतापूर्वक ट्रांसफर हो जाएगा।

कमजोर हो रहा ड्रैगन! चौतरफा मुसीबतों के बीच चीन को मिली एक और बैड न्यूज

चीन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। रेटिंग एजेंसी फिच ने उसके जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटा दिया है। इसमें 80 बीपीएस की भारी कटौती की गई है। चीन को पिछले कुछ दिनों से आर्थिक मोर्चे पर एक के बाद एक कई झटके लग रहे हैं।

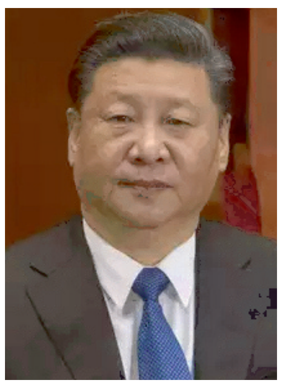

नई दिल्ली। संकटों से जूझ रही चीन की इकॉनमी (China Economy) के लिए एक और बुरी खबर आई है। रेटिंग एजेंसी फिच (Fitch) ने फाइनेंशियल ईयल 2023 के लिए चीन की जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को कम कर दिया है। पहले इसके 5.6 परसेंट रहने का अनुमान था लेकिन इसमें 80 बीपीएस की कमी की गई है। यानी चालू फाइनेंशियल ईयर में चीन की इकॉनमी के 4.8 परसेंट की रफ्तार से बढ़ने का अनुमान है। हालांकि एजेंसी ने चीन की लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी इश्यूर डिफॉल्ट रेटिंग्स ए+ को बरकरार रखा है। चीन में अगस्त में लगातार पांचवें महीने फैक्ट्री एक्टिविटीज में गिरावट आई है। चीन की सरकार पर सुस्त होती इकॉनमी में जान फूंकने का दबाव बढ़ रहा है। इसके लिए पॉलिसी सपोर्ट बढ़ाने की मांग की जा रही है।

जून में एसएंडपी ग्लोबल ने भी चीन के इकॉनमिक ग्रोथ के अनुमान को घटा दिया था। एजेंसी के मुताबिक चीन की जीडीपी ग्रोथ 2023 में 5.2 परसेंट रह सकती है। इसके बाद गोल्डमैन सैश और दूसरे बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकों ने भी चीन की रेटिंग में कटौती की थी। चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी है। हाल के महीनों में इकॉनमी के मोर्चे पर चीन को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। रियल एस्टेट गहरे संकट में है, इंडस्ट्रियल आउटपुट और रिटेल सेल्स ग्रोथ अनुमानों से कम है और युवाओं की बेरोजगारी 20.8 परसेंट के रेकॉर्ड पर पहुंच गई है। इस साल चीन की जीडीपी ग्रोथ 4.4 परसेंट से 6.2 परसेंट रहने का अनुमान है। चीन की सरकार ने पांच परसेंट ग्रोथ का अनुमान जताया है।

आज आएंगे भारत के आंकड़े

इस बीच भारत की पहली तिमाही के जीडीपी के आंकड़े आज जारी होंगे। ब्लूमबर्ग के अर्थशास्त्रियों के बीच कराए गए एक सर्वे के मुताबिक जीडीपी ग्रोथ 7.8 परसेंट पहुंच सकती है। आरबीआई की मॉनीटरी पॉलिसी ने पहली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ आठ परसेंट रहने का अनुमान जताया है। पहली तिमाही में एफडीआई में 34 परसेंट की गिरावट आई है और यह 10.94 अरब डॉलर रहा। पिछले साल की समान अवधि में यह 16.59 अरब डॉलर रही थी।

G20: शिखर सम्मेलन का मुख्य आयोजन स्थल है 'भारत मंडपम', मेहमानों के लिए की गई हैं खास तैयारियां

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। G20 शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली समेत एनसीआर तैयार है। शिखर सम्मेलन को ऐतिहासिक बनाने के लिए मुख्य आयोजन स्थल भारत मंडपम में G20 देशों की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने की व्यवस्था की गई है।

दरअसल, 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन होने जा रहा है और इसके लिए प्रगति मैदान में इंटरनेशनल एग्जिबिशन कम कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है, जिसे भारत मंडपम नाम दिया गया है।

इसमें भारतीय रिजर्व बैंक का एक प्रदर्शनी मंडप भी लगाया गया है। इसमें यूपीआई वन वर्ल्ड और सैन्ट्रल बैंक डिजिटल करन्सी सहित अनेक वित्तीय सुविधाए प्रदर्शित की जाएगी। रिजर्व बैंक के डिजिटल रूपया और इसकी यात्रा पर एक वीडियो भी दिखाया जायेगा। प्रदर्शनी में भाग ले रहे चुनिन्दा बैंक डिजिटल रूपया लेन-देन का प्रत्यक्ष प्रदर्शन भी करेंगे।

रूट्स टू रूट्स नामक प्रदर्शनी

इसके अलावा राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय G20 शिखर सम्मेलन के दौरान रूट्स टू रूट्स नामक प्रदर्शनी आयोजित करेगा। G20 नेताओं की पतनियां इस प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगी। संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने बताया कि इसमें देशभर की दुर्लभ कलाकृत्तियों को प्रदर्शित किया जायेगा। इस प्रदर्शनी का उददेश्य भारत के सांस्कृतिक गौरव को विश्व के मानचित्र पर लाना है। प्रदर्शनी में विभिन्न सरकारी संग्रहालयों और दीर्घाओं की भारतीय कलाकृतियों और मूर्तियों को दर्शाया जायेगा।

भारत मंडपम में 'शिल्प बाजार'

G20 आयोजन स्थल भारत मंडपम में 'शिल्प बाजार' लगाया जा रहा है। इसमें एक जिला एक उत्पाद, जीआई-टैग वाली वस्तुओं और महिलाओं तथा आदिवासी कारीगरों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

इस शिल्प बाजार में लगभग 30 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ-साथ खादी ग्राम एवं उद्योग आयोग, ट्राइफेड, सरस आजीविका जैसे केन्द्रीय एजेंसिया भी भाग ले रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों के सामने भारतीय कारीगरों के कौशल और उत्कृष्ट कारीगरी को प्रदर्शित करने के लिए, लाइव प्रदर्शनी की भी योजना तैयार की गई है।

वहीं, उत्तर पूर्व की असाधारण हस्तशिल्प और हथकरघा वस्तुओं को प्रदर्शित करने के लिए एक 'फोकस नॉर्थ ईस्ट' स्टॉल स्थापित किया जा रहा है। देशभर से राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं सहित लाइव कारीगर कला और शिल्प का प्रदर्शन किया जाएगा।

आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय मीडिया केन्द्र

वहीं सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने G20 शिखर सम्मेलन से पहले अन्तर्राष्ट्रीय मीडिया केन्द्र और प्रसार भारती के कमान केन्द्र की समीक्षा की। उनके साथ विदेश मंत्रालय, प्रसार भारती तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संवर्धन संगठन के अधिकारी भी थे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विश्व की सभी प्रमुख शक्तियों की मेजबानी करना देश के लिए अब तक का सबसे बड़ा अवसर होगा। उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन के मुख्य परिसर भारत मंडपम के निकट आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय मीडिया केन्द्र बनाया गया है।

दुनियाभर के जो हमारे मीडियाकर्मी आएंगे, उनके सुविधाओं से लैस पूरा एरिया होगा और शायद ही कहीं पर मीडिया सेंटर मैन लीडर समिट के पास इतना हो जितना यहां पे किया गया है। ये भी उनके लिए बहुत बड़ा आकर्षण है।

वाल्मिकी कल्याण बोर्ड का गठन के गठन की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को सौंपा पत्र

अनूप कुमार शर्मा, भीलवाड़ा। अखिल राजस्थान सफाई मजदूर कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री कमलेश कोटियाणा (वाल्मीकि) ने वाल्मिकी कल्याण बोर्ड के गठन की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के भीलवाड़ा प्रवास के दौरान पत्र सौपा। प्रदेश महामंत्री कमलेश कोटियाणा (वाल्मीकि) ने बताया कि सरकार द्वारा अभी हाल ही में विभिन्न समाजों का बोर्ड/ आयोग का गठन करने की घोषणा की गई है जो क्रियान्विति की ओर है। सरकार द्वारा निम्न बोर्ड जिसमें महात्मा ज्योतिबा फुले, रजक कल्याण, वीर तेजाजी किसान कल्याण, स्वर्ण रजत कला विकास, मेजर दलपत सिंह कल्याण, तेल-घाणी विकास, अवंति बाई लोधी, लव-कुश बोर्ड, श्रमण संस्कृति, निर्धनों के पुनर्वास आदि बोर्डो का गठन अभी हाल ही में किया गया है। कांग्रेस द्वारा चुनाव घोषणा पत्र में वाल्मिकी कल्याण बोर्ड के गठन का आश्वासन दिया गया था। कांग्रेस सरकार का कार्यकाल लगभग पूर्ण होने को है परन्तु आज दिवस तक वाल्मिकी कल्याण बोर्ड का गठन नहीं किया गया है। अतः जल्द से जल्द वाल्मिकी कल्याण बोर्ड के गठन की मांग पत्र के माध्यम से की गई।

' भारत ड्रोन शक्ति 2023'की सह-मेजबानी करेंगे भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया

नई दिल्ली। ड्रोन तकनीक ने दक्षता को बढ़ाते हुए, जोखिम को कम करके और क्षमता संवर्द्धन के साथ नागरिक और रक्षा क्षेत्रों में क्रांति ला दी है। भारत सैन्य और नागरिक दोनों क्षेत्रों में ड्रोन के उपयोग में वृद्धि का साक्षी बन रहा है। भारतीय वायुसेना खुफिया निगरानी और टोही कार्यों के लिए व्यापक स्तर पर रिमोट से संचालित विमानों का उपयोग कर रही है।

भारत में उभरते ड्रोन डिजाइन और विकास क्षमताओं में इसका विश्वास मेहर बाबा स्वार्म ड्रोन प्रतिस्पर्धा जैसी पहलों से हुआ है। इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से स्वदेशी क्षमता का दोहन करने का प्रयास किया गया है। भविष्य में भी इस तरह की प्रतियोगिता का आयोजन करने की तैयारी जारी है।

इन मानवरहित प्लेटफार्मों का उपयोग करने में अपने समृद्ध अनुभव का लाभ लेने के लिए, भारतीय वायुसेना 'भारत ड्रोन शक्ति 2023' की सह-मेजबानी करने के लिए ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी कर रही है। इस कार्यक्रम का आयोजन 25 और 26 सितंबर 2023 को हिंडन (गाजियाबाद) में एलएएफ के एयरबेस पर किया जाएगा, जिसका भारतीय ड्रोन उद्योग द्वारा लाइव हवाई प्रदर्शन किया जाएगा।

'भारत ड्रोन शक्ति 2023' भारतीय ड्रोन उद्योग की पूरी क्षमता के साथ 50 से अधिक लाइव हवाई प्रदर्शनों की मेजबानी करेगा, जिसमें सर्वेक्षण ड्रोन, कृषि ड्रोन, आग दमन ड्रोन, सामरिक निगरानी ड्रोन, हेवी-लिफ्ट लॉजिस्टिक्स ड्रोन, लोटरिंग मूनिशन सिस्टम का प्रदर्शन, ड्रोन समूह और काउंटर-ड्रोन के साथ-साथ 75 से अधिक ड्रोन स्टार्ट-अप और कॉरपोरेट्स की भागीदारी होगी। इस कार्यक्रम में केंद्र सरकार, राज्य सरकार विभागों, सार्वजनिक और निजी उद्योगों, सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, मित्र देशों के प्रतिनिधियों, शिक्षाविदों और छात्रों एवं ड्रोन के प्रति जिज्ञासा रखने वाले लगभग 5,000 लोगों के उपस्थित होने की उम्मीद है। इस आयोजन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि 'भारत ड्रोन शक्ति 2023' 2030 तक वैश्विक ड्रोन केंद्र बनने की भारत की प्रतिबद्धता को बढ़ावा देगा।

Asia Cup: फिर आमने-सामने होंगे भारत-पाक, 10 सितंबर को कोलंबो में होगा मुकाबला

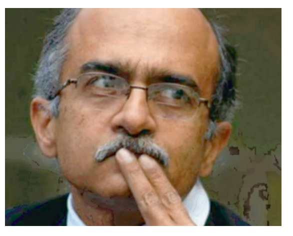

नई दिल्ली। एशिया कप में अब तक भारत अपने दो मुकाबले खेल चुका है। जिसमें पहला पाक के साथ बारिश की वजह से टाइ हो गया। वहीं दूसरे मैच में नेपाल को 10 विकेट से मात देते हुए सुपर 4 में पहुंच चुका है। ऐसे में अब मौजूदा एशिया कप के सुपर 4 चरण आज से शुरू हो रहा है, जिसमें चार टीमें महाद्वीपीय टूर्नामेंट के अगले चरण के लिए आमने-सामने हैं। मंगलवार को अफगानिस्तान पर रोमांचक जीत के बाद, सह-मेजबान श्रीलंका ने टूर्नामेंट के सुपर 4 चरण में जोरदार तरीके से प्रवेश किया।

सुपर 4 के लिए ग्रुप ए से भारत-पाक

दरअसल, चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान और भारत पहले ही ग्रुप ए से सुपर 4 चरण के लिए क्वालीफाई कर चुके हैं, और अब ग्रुप बी से श्रीलंका और बांग्लादेश दो टीमें हैं जिन्होंने अन्य दो स्थान हासिल किए हैं। चार टीमें अब सुपर 4 चरण के दौरान तीन और मैच खेलेंगी ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि 17 सितंबर को कोलंबो में होने वाले एकमात्र फाइनल में कौन सी दो टीमें पहुंचेंगी।

10 सितंबर को भारत-पाक मुकाबला

सुपर 4 चरण की शुरुआत के लिए पाकिस्तान लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में बांग्लादेश की मेजबानी करेगा। इसके बाद बांग्लादेश 9 सितंबर को आर. प्रेमदासा स्टेडियम में श्रीलंका से भिड़ेगा। चिर प्रतिद्वंद्वी भारत और पाकिस्तान के बीच टूर्नामेंट का दूसरा मैच 10 सितंबर को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में होगा, इससे पहले रोहित शर्मा की टीम दो दिन बाद 12 सितंबर को श्रीलंका से खेलने के लिए उसी स्थान पर लौटेगी। इसके बाद श्रीलंका 13 सितंबर को कोलंबो में एक महत्वपूर्ण मुकाबले में पाकिस्तान से भिड़ेगा। सुपर 4 चरण का आखिरी मैच 15 सितंबर को भारत और बांग्लादेश के बीच होगा।

कुल 6 सुपर फोर मैचों में से एक लाहौर में होगा जबकि बाकी पांच कोलंबो में होंगे। सुपर 4 चरण के अंत में दो अग्रणी टीमें रविवार, 17 सितंबर को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में फाइनल में भिड़ेंगी।

सुपर 4 के लिए मैच शेड्यूल:

6 सितंबर: पाकिस्तान vs बांग्लादेश, गद्दाफी स्टेडियम, लाहौर
9 सितंबर: श्रीलंका vs बांग्लादेश, आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो,
10 सितंबर: पाकिस्तान vs भारत, आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो
12 सितंबर: भारत vs श्रीलंका, आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो
14 सितंबर: पाकिस्तान vs श्रीलंका, आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो
15 सितंबर: भारत vs बांग्लादेश, आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो

निशुल्क सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा परामर्श शिविर 10 को महेश छात्रावास में

गुजरात के प्रथम हृदय प्रत्यारोपण सर्जन डॉ धीरेंन शाह शिरकत करेंगे

अनूप कुमार शर्मा

भीलवाड़ा। जिला माहेश्वरी सभा एवं मैरिंगो सिम्स हॉस्पिटल, अहमदाबाद के तत्वाधान विशाल निशुल्क सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा परामर्श शिविर 10 सितंबर रविवार को प्रातः 9 बजे से 1:30 बजे तक स्थानीय नेहरू रोड, रोडवेज बस स्टैंड के पास स्थित महेश छात्रावास में आयोजित होगा जिला अध्यक्ष अशोक बाहेती एवं मंत्री रमेश राठी ने बताया कि निशुल्क सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा परामर्श शिविर में 14 विभिन्न बीमारियों के सुपर स्पेशलिटी वरिष्ठ चिकित्सक रोगियों को निशुल्क परामर्श देंगे जिसमें हृदय रोग, मस्तिष्क रोग, रीड के विशेषज्ञ, पेट संबंधी रोग, फेफड़े एवं पल्मोनोलॉजिस्ट , कैंसर रोग, ऑर्थोपेडिक एवं ज्वाइंट रिप्लेसमेंट न्यूरोलॉजिस्ट, मूत्र रोग संबंधी बीमारियां के अति वरिष्ठतम चिकित्सक भीलवाड़ा में अपनी निशुल्क सेवाएं देंगे शिविर प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि शिविर में चिकित्सकों के परामर्श पर निशुल्क शुगर जांच, ब्लड प्रेशर, ई सी जी, बीएमआई (बोन डेंसिटी) की जांच भी की जाएगी रोगियों को परामर्श से पूर्व रजिस्ट्रेशन करना होगा एवं अहमदाबाद के वरिष् चिकित्साको द्वारा शनिवारको भीलवाड़ा के चिकित्सकों के साथ सीएमई (क्लीनिकल मेडिकल एजुकेशन) का विशेष आयोजन भी होगा।

ओड़िशा में सुप्रीम कोर्ट वकील श्री प्रशांत भूषण

मनोरंजन सासमल , ओड़िशा

भुबनेस्वर् : सामाजिक कार्यकर्ता और सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण पुरी में आयोजित किसान रैली में शामिल होने के लिए ओडिशा पहुंचे हैं। वेदांता यूनिवर्सिटी के खिलाफ संघर्ष में किसानों की जीत हुई है. इसके लिए प्रशांत भूषण का जोरदार स्वागत किया गया है. ओडिशा सरकार ने वेदांत विश्वविद्यालय के लिए पुरी, कोणार्क समुद्र तट क्षेत्र में लगभग 6 हजार एकड़ कृषि भूमि बहुत कम कीमत पर अधिग्रहित की।

इससे 6000 परिवार और 30000 लोग सीधे तौर पर प्रभावित हुए. हालाँकि, 2011 से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील वेदांता यूनिवर्सिटी के ख़िलाफ़ लड़ते रहे। आख़िरकार प्रशांत भूषण और किसानों ने सुप्रीम कोर्ट में क़ानूनी लड़ाई जीत ली. सुप्रीम कोर्ट ने वेदांत विश्वविद्यालय के नाम पर राज्य सरकार द्वारा जब्त की गई महाप्रभु श्रीजगन्नाथ और किसानों की जमीन को तत्काल वापस करने को कहा। इसके अलावा, अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो अगले 20 वर्षों में ओडिशा में लौह अयस्क खनन समाप्त हो जाएगा। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में यह जानकारी दी. इसके अलावा खनन पर रोक लगाने की गुहार के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई. प्रशांत भूषण का तर्क है कि मिट्टी के नीचे खनिज सीमित मात्रा में हैं. हम अपनी इच्छा से खदानों का विस्तार या निर्माण नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि मिट्टी के नीचे खनिजों की मात्रा सीमित है। प्रशांत भूषण ने कहा, इसलिए, अगर इसे जानबूझकर उठाया गया है, तो यह एक न एक दिन खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ वकील ने कहा, इसे तुरंत रोका जाना चाहिए।

झारखंड में पहली बार आने वाला है विस्टाडोम कोच, यात्री ले सकेंगे सफर का भरपूर आनंद

अनूप कुमार शर्मा

नई दिल्ली। झारखंड में रेल यात्रियों की सहूलियत में एक और इजाफा होने वाला है। दरअसल, झारखंड में रेल यात्रियों को विस्टाडोम कोच में सफर करने का अनुभव मिलने वाला है। इसके लिए झारखंड के रांची रेल मंडल में पहली बार विस्टाडोम कोच आने वाला है। यह कोच न्यू गिरिडीह-रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस में लगेगा।

12 सितंबर को रांची पहुंचेगी ट्रेन

12 सितंबर को यह विशेष रेलगाड़ी एक विस्टाडोम कोच के साथ रांची पहुंचेगी। इसे सुबह 10 बजे गिरिडीह में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। यह कोच बेहद खूबसूरत और सुखद अहसास कराने वाला होगा।

ये होगा ट्रेन रूट

इस कोच के माध्यम से सरकार पर्यटकों को आकर्षित करने पर फोकस कर रही है। यह ट्रेन जमुआ, धनवार, महेशपुर, कोडरमा, हजारीबाग टाउन, बड़काकाना-मेसरा और टाटीसिल्वे होते रांची तक का सफर करेगी।

यात्री ले सकेंगे सफर का भरपूर आनंद

इसके पीछे उद्देश्य है कि विस्टाडोम से यात्री सफर का पूरा आनंद ले सकें। रास्ते में पड़ने वाले मनोरम और प्राकृतिक सौंदर्य को महसूस कर सकें। ट्रेन में कुल 13 कोच होंगे। न्यू गिरिडीह-रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन दूसरी रेलगाड़ी हजारीबाग टाउन से जुड़ेगी।

पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

रांची रेल मंडल के सीनियर डीसीएम निशांत कुमार ने यह विवरण साझा किया है। उन्होंने कहा कि यह पहला मौका होगा, जिसके तहत किसी ट्रेन में विस्टाडोम कोच जोड़ा जा रहा है। ऐसा पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जा रहा है।

कैसे होंगे विस्टाडोम कोच ?

विस्टाडोम कोच में बड़े ग्लास की खिड़कियां हैं। इनमें छह पारदर्शी होंगी। यह यात्री को साइड के साथ ऊपर की तरफ के दृश्य देखने में मदद करेंगी। कोच का निर्माण आईसीएफ ने किया है। इस कोच में 42 से 44 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था की गई है। इसकी सबसे बड़ी खासियत होगी इसकी शानदार सीट 180 डिग्री पर घूम सकेगी। शानदार पुशबैक होगी।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी–18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए–4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली– 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 98117320959 .
किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय में ही होगा। समाचार पत्र में प्रकाशित किये गये मसौदे के लिए लेखक स्वयं जिम्मेदार हैं। Title Code : DELHIN28985. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023